साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 6 • कठुआ, शनिवार 7 फ़रवरी 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

जम्मू और कश्मीर सरकार कैंसर मरीज़ों के लिए बेहतरीन सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध : सीएम उमर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू में विश्व कैंसर दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया, और कैंसर मरीज़ों के साथ–साथ हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने में सरकार की सक्रिय भूमिका को दोहराया।

यह कार्यक्रम ळडब जम्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर फाइट्स कैंसरश थीम के तहत विश्व कैंसर दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुश्री सकीना इटू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता, उरी के विधायक डॉ. सज्जाद शफी, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉ.

सैयद आबिद रशीद, प्रिंसिपल ळडब जम्मू डॉ. आशुतोष गुप्ता, जाने–माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. समीर कौल, वरिष्ठ प्रोफेसर, डॉक्टर, फैकल्टी सदस्य और छात्र शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने एक ऐसे भविष्य की उम्मीद जताई जब दुनिया सच में विश्व कैंसर दिवस को उस दिन के रूप में मना पाएगी जब कैंसर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, ष्तब तक, हमें इस बीमारी को जितना हो सके उतना अच्छे से मैनेज करना होगा।

अपने निजी अनुभव साझा करते हुए, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैंसर के मरीज़ों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर के बारे में गहरी सहानुभूति से बात की। उन्होंने स्कैन के नतीजों का बेसब्री से इंतजार करने, अपने प्रियजनों को कीमोथेरेपी और रेडिएशन से गुजरते देखने, और इस बीमारी से परिवार के सदस्यों को खोने के दर्द को याद किया।

उन्होंने कहा, ष्यह बीमारी लोगों को डराती है, यह मरीज़ को डराती है, यह उनके परिवार को डराती है, न केवल बीमारी के पूर्वानुमान और इलाज

■ शेष पेज 2...

विपक्ष के नेता ने केंद्र की विदेश नीति की तारीफ की, राहुल गांधी की आलोचना की; पीडीपी विधायक ने विपक्ष की भूमिका का बचाव किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू तवी : जम्मू–कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और ठश्रच नेता सुनील शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की विदेश नीति की तारीफ की, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोकसभा में अपनी टिप्पणियों के जरिए देश की सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने हाल ही में भारत–अमे. रिका व्यापार समझौते और 2020 में भारत–चीन संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आला. `चना की। इसके कारण लोकसभा में लगातार दो दिन – सोमवार और मंगलवार को हंगामा हुआ और इस मुद्दे पर सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा।

शर्मा ने यहां रिपोर्टर्स से कहा, "भारत की फॉरेन पॉलिसी में सफलता दिख रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में दिख रहा है। राहुल गांधी जब हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं तो बच्चों की तरह बात करते हैं। वह देश की सिक्योरिटी पॉलिसी और आर्मी पर भी सवाल उठा रहे हैं।" उन्होंने कहा, ष्यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश के विपक्षी नेता देश की

■ शेष पेज 2...

सिविल सर्विसेज़ एग्जाम के नियम बदलते फ्रेमवर्क का हिस्सा : सरकार

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सिविल सर्विस परीक्षा के नियम एक बदलते फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं और सरकार बराबर मौका पक्का करने के लिए लगातार सुधार के साथ–साथ सुधार के उपाय भी कर रही है।

सिंह उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें सरकार के पास सिविल सर्विस (मेन) एग्जाम के हिस्से के तौर पर लद्दाख के कैंडिडेट्स को इंडियन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करने से छूट देने के किसी प्रपोज़ल के बारे में डिटेल्स मांगी गई थीं।

सिविल सर्विस परीक्षा हर साल तीन स्टेज में होती है दृ शुरुआती, मुख्य और इंटरव्यू दृ इसके लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (ले), इंडियन फॉरेन सर्विस (फै) और इंडियन पुलिस सर्विस (पै) वगैरह के ऑफिसर चुने जाते हैं।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का पेपर ज़रूरी नहीं है।

उनका जवाब इस सवाल पर आया कि क्या इन छह राज्यों के उम्मीदवारों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा

■ शेष पेज 2...

सीएस डुल्लू ने ट्रैफिक प्लान को रिजल्ट- ओरिएंटेड लागू करने पर जोर दिया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर मल्टी–डिसिप्लिनरी कमेटी (डक्ब) की मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में दोनों राजधानी शहरों में भीड़ कम करने, रोड सेफ्टी को मजबूत करने और ओव. रऑल अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने के मकसद से बनाए गए प्लान और प्रपा. `जल का रिव्यू किया गया।

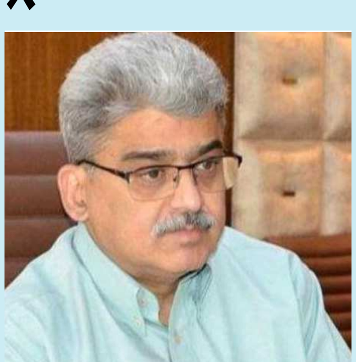

प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ट्रैफिक पुलिस और म्युनि. सिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनल करने और दूसरी कानूनी और प्रोसीजरल ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, पहचाने गए प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पर पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने डिपार्टमेंट को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने और जहाँ भी ज़रूरी हो, नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के तरीकों को समय पर लागू किया जा सके और सख्ती से लागू किया जा सके।

चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि क्योंकि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सलाह करके प्रोजेक्ट्स की पहचान पहले ही कर ली गई है, इसलिए अब सही बजट का इंतज़ाम करके उन्हें लागू करना शुरू करना ज़रूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि बजट बनाने का काम अभी चल रहा है। उन्होंने ट्रैफिक रूट, नो–पार्किंग ज़ोन और नो–हॉन बजाने वाले एरिया में बदलावों को नोटिफाई करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया ताकि लोगों में काफ़ी जागरूकता और नियमों का पालन पक्का हो सके।

होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चंद्राकर भारती ने सुझाव दिया कि सभी अप्रूव्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (ठत।च) प्लेटफॉर्म पर मैप किया जाए, ताकि उनकी प्रोग्रेस की अच्छे से मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग हो सके। कमिश्नर सेक्रेटरी, भ्न्क्क, मंदीप कौर ने डक्ब के टर्म्स ऑफ़

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

भारत किसानों के...

के कारण, बल्कि वित्तीय नतीजों के कारण भी।

कैंसर से लड़ने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने तीन प्रमुख जिम्मेदारियों के बारे में बताया।

उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने, अच्छी मेडिकल शिक्षा सुनिश्चित करने और डॉक्टरों और ऑन्कोलॉजिस्ट को कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में मदद करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य की पीढ़ियां एक दिन कैंसर को अतीत की बीमारी के रूप में याद करेंगी।

मुख्यमंत्री ने मजबूत स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि देर से पता चलने के कारण कैंसर अक्सर जानलेवा हो जाता है। उन्होंने कहा, ष्जल्दी स्क्रीनिंग ज़रूरी है ताकि इस भयानक बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।ष जम्मू और कश्मीर में मज़बूत इलाज की सुविधाएँ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम मरीज़ों को एडवांस्ड कैंसर इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर जाना पड़े। उन्होंने कहा, ष्हमारी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम मरीज़ों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए श्र–झ से बाहर जाना पड़े।ष

मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंसर मरीज़ों के लिए एक मज़बूत वित्तीय सुरक्षा जाल की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, क्योंकि इलाज का बोझ गरीबों पर बहुत ज़्यादा होता है।

यह आश्वासन देते हुए कि सरकार ऐसे कार्यक्रमों और वर्कशॉप से घ्मिलने वाले सभी सुझावों पर काम करेगी, उन्होंने कहा, ष्कृपया निशि. चंत रहें कि मेरी सरकार उनमें से एक भी सुझाव को नज़रअंदाज़ नहीं करेगी। हम अपने अस्पतालों में बेहतरीन सुविधाएँ और अपने मरीज़ों के लिए बेहतरीन सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।ष

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों द्वारा मेडिकल पेशे को चुनने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।

उन्होंने कहा, ष्हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने चुने हुए पेशे का अभ्यास करने के लिए सही माहौल और सही सुविधाएँ मिलें।ष

विपक्ष के नेता ने...

संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सवालिया निशान लगाते हैं।

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डस। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने गांधी का बचाव करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में सवाल उठाना डेमोक्रेटिक कामकाज का हिस्सा है और यह एक अपोज़िशन लीडर की ज़िम्मेदारी है।

वह गांधी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे लेटर पर रिएक्शन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर सदन में बोलने के उनके अधिकार को पहले कभी न देखे गए हनन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया था।

मेहदी ने कहा, "यह एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। वह एक ज़िम्मेदार अपोज़िशन लीडर हैं। उन्हें सरकार से सवाल करना होगा क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। इसलिए वह लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि संसद में गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें पार्टी की राजनीतिक लाइन से नहीं देखना चाहिए। मेहदी ने कहा, "संसद में वे जो भी सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए। इसे कांग्रेस या ठश्रच के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। एक डच और लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर, सवाल पूछना उनका हक है, चाहे वे देश के लिए ज़रूरी हों या सरकार के लिए।"

सिविल सर्विसेज़...

में क्वालिफाइंग भाषा के पेपर से छूट दी जाती है।

सिंह ने कहा कि यह परीक्षा न्च्ैब् हर साल डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा नोटिफ़ाई किए गए सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन (ब्ैम्) नियमों के अनुसार आयोजित करता है।

उन्होंने कहा, "ब्ैम् रूल्स–2025 के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए इंडियन लैंग्वेज का पेपर । ज़रूरी नहीं है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या लद्दाख के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स से ऐसी ही छूट देने का कोई प्रपोज़ल है, सिंह ने कहा कि ब्ैम् रूल्स एक डायनामिक और इवॉल्विंग फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं।

मंत्री ने कहा, "पूरे देश में उम्मीदवारों के लिए बराबर मौका पक्का करने के लिए, सरकार लगातार सुधार और सुधार के उपाय करती रहती है।"

सीएस डुल्लू ने...

रेफरेंस (ज्वत) बताते हुए, दोनों शहरों के लिए यहां लागू किए जा रहे बड़े ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के हिस्सों के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (प्ज्डै) को मजबूत करना, रोटरी, जंक्शन और ज्–पॉइंट बनाना, और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (प्ब्ब्ब्) के साथ इंटीग्रेशन करना शामिल है।

उन्होंने आगे बताया कि इस प्लान में लेन डिसिप्लिन पक्का करना और ई–चालान के ज़रिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई करना, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रूट परमिट कैंसल करना, इसके अलावा दूसरे ट्रैफिक सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर की पहचान करना शामिल है।

जैसा कि बताया गया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में अतिक्रमण कंट्रोल, ट्रैफिक फ्लो रेगुलेशन, भीड़ कम करने के उपाय जैसे वेंडिंग ज़ोन को दूसरी जगह ले जाना, पैदल चलने वालों के लिए कॉरिडोर की पहचान, डिवाइडर लगाना, बस स्टॉप और शेल्टर बनाना, प्ज वाले पार्किंग सिस्टम, सड़क की कैपेसिटी बढ़ाना, और सड़क सुरक्षा और एक्सीडेंट कम करने के उपाय लागू करना भी शामिल है।

इसके अलावा, इस प्लान में शिकारा और वॉटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट शुरू करने, फुटपाथ को बेहतर बनाने, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिशें, और जम्मू और श्रीनगर में असरदार और टिकाऊ ट्रैफिक मैनेजमेंट पक्का करने के लिए डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मीटिंग में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिनमें टूरिज्म और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी; प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम; कमिश्नर सेक्रेटरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (भ्–न्क्क); डिविजनल कमिश्नर, जम्मू/कश्मीर; इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ट्रैफिक; सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट; डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक, जम्मू/कश्मीर; सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, श्रीनगर/जम्मू; म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू और श्रीनगर के कमिश्नर; वाइस चेयरमैन, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (स्ब्ड।); वाइस–चेयरमैन, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (श्रक।); डायरेक्टर, अर्बन लोकल बॉडीज, और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल थे।

2000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे 120 भारतीय जवान... कैसे शैतान सिंह की रणनीति ने दुश्मन को धो डाला?

दिनेश पाठक

18 नवंबर की तारीख भारतीय सेना के उन अमर नायकों की याद दिलाती है जिन्होंने हिमालय की गोद में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ताकि देश का सम्मान अक्षुण्ण रहे. मेजर शैतान सिंह उन्हीं वीरों के अग्रणी योद्धा थे, जिन्होंने 1962 के भारत–चीन युद्ध में 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों के साथ मिलकर लगभग 2000 चीनी सैनिकों का सामना किया.

संयोग देखिए कि 18 नवंबर उनकी पुण्यतिथि है और इसी प्रसंग पर आधारित फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर को रिलीज हो रही है, जो उन गुमनाम नायकों की बहादुरी को नई पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास है.

तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए, अब धमाका शुरू करूं... ट्रेलर में श्धु. रंधरश की हुंकार, 4 मिनट में श्पाकिस्तानश पर तगड़ा वार!

आइए जानते हैं मेजर शैतान सिंह की जिंदगी, उनकी सैन्य रणनीतियों और रेजांग ला की उस अद्भुत लड़ाई की कहानी, जिसने इतिहास में भारतीय साहस की मिसाल कायम की. आज भी भारतीय सेना के जवान–अफसर तो उन्हें गर्व से याद करते ही हैं, देश भी अपने उस वीर सपूत को नमन करता है.

बचपन से रणभूमि तक का सफर

शैतान सिंह का जन्म राजस्थान के जोधपुर ज़िले के बानासर के एक राजपूत सैन्य परंपरा वाले परिवार में एक दिसंबर 1924 को हुआ. बचपन से ही अनुशासन, सादगी और देश–प्रेम उनके घर–आंगन की हवा में घुला हुआ था. पिता भी सेना से जुड़े रहे, इसलिए सैनिक जीवन की कहानियां उनके लिए कोई रोमांटिक कल्पना नहीं, बल्कि जीती–जागती प्रेरणा थीं.

युवा होने तक शैतान सिंह का व्यक्तित्व बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था. कम बोलने वाले, सीधे–सादे, पर निर्णय के क्षण में अद्भुत स्पष्टता रखने वाले. कठोर वातावरण में पले होने के कारण उन्हें प्रतिकूल मौसम, भूख–प्यास या तकलीफों की परवाह कम रहती. उनका सपना था कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करें, और यह सपना ज्यादा देर तक सपना नहीं रहा. वे भारतीय सेना में शामिल हुए और कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े. वही रेजिमेंट जो बाद में रेजांग ला की लड़ाई में इतिहास रचने वाली थी.

मेजर शैतान सिंह.

कुमाऊं रेजिमेंट और शैतान सिंह की पहचान

कुमाऊं रेजिमेंट का स्वभाव ही कठिन इलाकों में तैनाती और दुश्मन के सामने डटकर खड़े रहने का रहा है. जवानों में मेजर शैतान सिंह की छवि एक ऐसे अधिकारी की थी जो आदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण पेश करता है. वे जवानों के साथ उसी कठोरता से रहते, वही खाना, वही ठंड, वही कंटीली चढ़ाइयां. अभ्यास के दौरान वे खुद सबसे आगे चलते, बोझ उठाते, फायरिंग रेंज में सटीक निशाना लगाते और अपने सैनिकों को बारबार समझाते कि सीमा पर कमजोरी की कोई जगह नहीं. दुश्मन संख्या में बड़ा हो सकता है, पर दिल से बड़ा नहीं. उनके शांत स्वभाव के पीछे एक दृढ़ नेतृत्व छिपा था. वे न तो शोर मचाते थे, न दिखावा करते थे, पर जब वे कोई फैसला लेते तो पूरा प्लाटून उस फैसले को आखिरी सत्य मानकर चल पड़ता.

1962 का चीन से युद्ध, घिरता हुआ तूफ़ान

साल 1962 में भारत–चीन संबंधों में तनाव चरम पर था. सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट न होने और राजनीतिक मतभेदों के कारण दोनों देशों की सेनाएं ऊंचाई वाले इलाकों में आमनेसामने आ खड़ी हुईं. रेजांग ला यह नाम उस समय भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था. लद्दाख के चुशुल सेक्टर के पास स्थित यह दर्रा 16 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर है, जहां सांस लेना भी चुनौती है. तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, तेज़ बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और हर तरफ पत्थरों–बर्फ की दुनिया. यहीं 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी को तैनात किया गया, जिसके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह. ऊपर से संसाधन सीमित.

भारी हथियार कम, गोला–बारूद सीमित और वायरलेस संचार तक पूरी तरह भरोसेमंद नहीं. लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय सैनिकों के हौसले बुलंद थे. उन्हें पता था कि अगर यह दर्रा टूट गया, तो चुशुल और आगे के बेस पर सीधा खतरा आएगा.

फिल्स 120 बहादुर शैतान सिंह पर बनी है

रेजांग ला की एक रात जब दुश्मन चुपके से बढ़ा

18 नवंबर 1962 की रात असाधारण रूप से शांत थी. आसमान काला, हवा में बर्फ़ के महीन कण, और दूरी पर कहीं–कहीं चीनी पोस्टों की हल्की हलचल. मेजर शैतान सिंह जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है. उन्होंने अपने जवानों को अंतिम बार तैनाती की समीक्षा के साथ निर्देश दिए. हर प्लाटून को चट्टानों और चढ़ाइयों के हिसाब से पोज़िशनिंग के आदेश थे. फायर फील्ड यानी किनकिन कोणों से दुश्मन को रोका जा सकता है, इसकी साफ योजना बना रखी थी.

रिज़र्व गोला–बारूद की गणना, घायल होने की स्थिति में एक–दूसरे की मदद के तरीके पर भी निर्देश स्पष्ट थे. चीनी सेना संख्या में लगभग दस गुना अधिक थी. उनके पास मोर्टार, भारी मशीनगनें और बेहतर संचार साधन भी थे.

उन्होंने भारतीय पोस्ट को चारों तरफ से घेरने, पीछे से घुसकर आपूर्ति लाइनों को तोड़ने और सामने से भारी फायरिंग करने की योजना बनाई. सोच यह थी कि 120 भारतीय सैनिक डरकर पीछे हट जाएँगे या आत्मसमर्पण कर देंगे.

कम सैनिक लेकिन घातक मोर्चाबंदी

मेजर शैतान सिंह की रणनीति का सबसे बड़ा आधार था भौगोलिक स्थिति का पूरा उपयोग. उन्होंने अपने सेक्शन इस प्रकार तैनात किए कि दुश्मन ऊपर चढ़ते ही उनके निशाने पर आ जाए. पत्थरों की आड़ में छिपे भारतीय सैनिक दुश्मन को निकट आने का इंतज़ार करते रहे, ताकि हर गोली का उपयोग सटीक हो.

सीमित संख्या में होने के बावजूद उन्होंने मोर्चों को इस तरह बांटा कि दुश्मन चाहे जिस दिशा से आए, उसे किसी न किसी सेक्शन की क्रॉस फायरिंग झेलनी पड़े. इससे चीनी सैनिकों की संख्या का लाभ कुछ हद तक निष्प्रभावी हो गया. रात के सन्नाटे में उन्होंने आदेश दिया कि जब तक साफ़ दिखे नहीं, गोली मत चलाना. इसका परिणाम यह हुआ कि प्रारंभिक हमले में भारतीय जवाबी फायर अत्यंत प्रभावी रहा और चीनी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा.

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नया वर्ष, नई गति : मोदी सरकार के 2025 के सुधारों से भारत की अगली छलांग

श्री पीूष ेा;ल

नया वर्ष भारत के वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए नई ऊर्जा, नए विश्वास और नए आत्मविश्वास का संदेश लेकर आया है। वर्ष 2025 में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक और दूरदर्शी कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन सुधारों का उद्देश्य केवल व्यापार और निवेश को गति देना नहीं है, बल्कि छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स, किसानों, कारीगरों और आम नागरिक के जीवन को सरल बनाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार और आत्मनिर्भरता के माध्यम के रूप में देखा है। आज भारत में दो लाख से अधिक सरक.ारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की दसवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स न केवल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत, लचीला और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं। यह स्टार्टअप्स को समर्थन देने की नीति, सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेज आर्थिक विकास के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना और हर नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना है, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के लिए।

वर्ष 2025 भारत की उस परिवर्तनकारी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो 2014 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे साहसिक फैसले लिए, जिन्होंने भारत के कारोबारी माहौल को पूरी तरह बदल दिया। इन सुधारों की खास बात यह रही कि हर नीति का केंद्र आम नागरिक रहा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर जमीन पर दिखे। इसी का परिणाम है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद और जिम्मेदार भागीदार के रूप में पहचाना जा रहा है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के निर्यात ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वर्ष 2024दृ25 में भारत का कुल निर्यात छह प्रतिशत बढ़कर 825.25 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय उद्योग और निर्यातक कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े हैं। निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

जन विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत 71 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया, जिनमें से कुछ 1886 के समय के थे। जन विश्वास पहल के अंतर्गत छोटे–मोटे अपराधों के लिए आपराधिक प्रावधानों को हटाया गया, जिससे कारोबा.रियों और उद्यमियों को अनावश्यक भय से मुक्ति मिली। इन सुधारों का उद्देश्य शासन को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है ताकि भारत का कानूनी ढांचा तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो सके। आने वाले समय में सैकड़ों अन्य प्रावधाना. ें की समीक्षा कर उन्हें भी सरल बनाया जाएगा।

वर्ष 2024 के मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित पाँच महत्वपूर्ण विधेयकों ने शिपिंग और पोर्ट्स क्षेत्र में बड़े सुधार किए। इन कानूनों से दस्तावेजी प्रक्रियाएँ सरल हुईं, विवाद निपटान में आसानी आई और लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आई। वाणिज्य क्षेत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पारदर्शी और सहायक नीतियों के माध्यम से निर्यातकों को निरंतर समर्थन दिया। इन पहलों से व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप्स की उद्यमशीलता को नई उड़ान मिली है, क्योंकि अब वे जटिल अनुपालनों और छोटे उल्लंघनों पर जेल जाने के डर से मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

भारत की व्यापार और निवेश रणनीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है 'लोकल फॉर ग्लोबल'। इसका अर्थ है स्थानीय उद्यमियों, विशेष रूप से छोटे कारोबा.रियों, स्टार्टअप्स, किसानों और कारीगरों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाना। इसी दृष्टि के तहत भारत ने पिछले वर्ष यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ तीन मुक्त व्यापार समझौते संपन्न किए। इन समझौतों से भारतीय उत्पादों को विकसित बाजारों में शुल्क मुक्त या कम शुल्क पर पहुँच मिली है। ये समझौते केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा युवाओं के लिए नए अवसर खोलने वाले हैं।

मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह जल्दबाजी में ऐसे समझौते नहीं किए, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हों। इसके बजाय, सरकार ने विकसित देशों के साथ संतुलित और लाभकारी समझौतों को प्राथमिकता दी। हर समझौते से पहले व्यापक हितधारक परामर्श किया गया, ताकि किसाना. ें, उद्योगों और छोटे व्यवसायों के हित सुरक्षित रहें। इन समझौतों में भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा की गई है, चाहे वह न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े डेयरी निर्यातक देश ही क्यों न हों।

इनके अतिरिक्त, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, के साथ 2024 में किए गए समझौते को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इन सभी समझौतों की एक समान विशेषता यह है कि भारतीय निर्यात को तत्काल या शीघ्र शुल्क राहत मिलती है, जबकि भारत अपने बाजार को धीरे–धीरे और संतु.लित तरीके से खोलता है। न्यूजीलैंड द्वारा अगले पंद्रह वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विद. ेशी निवेश की प्रतिबद्धता, इन समझौतों में शामिल नवाचारी निवेश प्रावधानों का प्रमाण है। यह निवेश कृषि, डेयरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, खेल और युवा विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक और समावेशी विकास को समर्थन देगा।

भारत आज एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले ग्यारह वित्तीय वर्षों में, 2024दृ25 तक, भारत ने 748 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो इससे पहले के ग्यारह वर्षों में प्राप्त 308 अरब अमेरिकी डॉलर से लगभग ढाई गुना है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में पाई थी, जिसे कभी दुनिया की 'फ्रैजाइल फाइव' में गिना जाता था। पूर्ववर्ती शासन के दौरान आर्थिक अस्थिरता के कारण कई विकसित देशों ने भारत के साथ व्यापार वार्ताएँ रोक दी थीं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त शासन, साहसिक सुधारों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल किया और भारत को व्यापार व निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाया।

वर्ष 2025 का अंत भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि के साथ किया। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अब जर्मनी को पीछे छोड़ने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचा है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने ऐतिहासिक श्रम सुधार किए, जिनके तहत 29 बिखरे हुए कानूनों को चार आधुनिक श्रम संहिताओं में समाहित किया गया। इनका उद्देश्य उचित वेतन, समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा देना भी है।

वस्तु एवं सेवा कर में किए गए सुधारों से हर भारतीय नागरिक को लाभ मिला है। दो स्लैब की स्वच्छ और सरल संरचना ने घरेलू उपभोक्ताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, किसानों और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम किया है। यह सुधार पारदर्शिता बढ़ाने और कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आगे की राह भी उतनी ही उत्साहजनक है। वर्ष 2025 घरेलू उद्यम और वैश्विक मांग के बीच, नीति सुधार और डिजिटल सशक्तिकरण के बीच, तथा छोटे व्यवसायों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच सेतु निर्माण का वर्ष रहा। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा के नेतृत्व में गठित एक पैनल व्यापक सुधारों का अध्ययन कर रहा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की सुधार एक्सप्रेस को और गति मिलेगी।

भारत आज स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, जहाँ प्रतिस्पर्धी व्यापार, नवाचारी उद्योग और मजबूत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो। देश के निर्यातकों, निर्माताओं, किसानों और सेवा प्रदाताओं की सफलता ही राष्ट्र की सफलता है। भारत केवल भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उसे आकार दे रहा है। निर्णायक नेतृत्व, साहसिक सुधारों और स्पष्ट वैश्विक रणनीति के साथ भारत अपने दम पर, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शिवखोड़ी गुफा का रहस्य

कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ मां पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश भी रहते हैं। वह आज भी सपरिवार कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। लेकिन माना जाता है कि जम्मू-कश्मीर की एक पवित्र गुफा में भगवान शिव वास करते हैं।

राम सिंह गुलेरिया

आज भी व्यापक रूप से यह मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश को शिव का परम धाम माना गया है, जहाँ माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय उनके साथ वास करते हैं। शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में कैलाश पर्वत को शिवलोक के रूप में वर्णित किया गया है। किंतु इन मान्यताओं के समानांतर एक और विश्वास भी है, जो विशेष रूप से जम्मू–कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव का निवास केवल कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जम्मू–कश्मीर की एक रहस्यमयी और पवित्र गुफा में भी विराजमान हैं।

यह पवित्र गुफा स्थानीय लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध है और इसे "शिवखोड़ी गुफा" के नाम से जाना जाता है। यह गुफा मात्र एक प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि आस्था, श्रद्धा और भय का अद्‌भुत संगम है। स्थानीय जनमान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने निवास किया था और जहाँ आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति अनुभव की जाती है।

शिवखोड़ी गुफा जम्मू से लगभग एक सौ चालीस किलोमीटर की दूरी पर उधमपुर ज़िले के पास स्थित है। दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और ऊँचाई पर स्थित होने के कारण यह स्थान अपने आप में रहस्यमय प्रतीत होता है। यह गुफा देखने में साधारण नहीं है, बल्कि एक लंबी और संकरी सुरंग जैसी प्रतीत होती है। इसकी लंबाई लगभग दो सौ मीटर, चौड़ाई लगभग एक मीटर और ऊँचाई दो से तीन मीटर के बीच मानी जाती है। गुफा के भीतर प्रवेश करना आसान नहीं है, और इसी कारण इसके भीतर जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं।

स्थानीय मान्यता के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस गुफा के भीतर गहराई तक प्रवेश करता है, वह आज तक वापस नहीं लौटा। यही विश्वास इस गुफा को और भी रहस्यमय बनाता है। हालांकि, गुफा के मुख तक दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वे बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं।

यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में साधु–संत इसी गुफा के माध्यम से अमरनाथ गुफा तक जाया करते थे। किंतु कलियुग में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, जो इस गुफा में प्रवेश कर उस पार तक पहुँच सका हो। इस धारणा ने शिवखोड़ी गुफा को लोककथाओं और आस्थाओं का केंद्र बना दिया है।

शिवखोड़ी गुफा की सबसे विशेष बात यह है कि इसके भीतर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि चट्टानों के प्राकृतिक आकार और संरचना से स्वयं बना हुआ माना जाता है। अमरनाथ गुफा में जहाँ बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है, वहीं शिवखोड़ी गुफा में यह शिवलिंग पत्थर की प्राकृतिक संरचना के रूप में विद्यमान है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर पूजन करते हैं।

गुफा के भीतर अन्य प्राकृतिक आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। इनमें नंदी की आकृति, माता पार्वती से मिलती–जुलती आकृतियाँ और सर्प जैसी संरचनाएँ शामिल हैं। गुफा की छत पर सर्पाकार आकृतियों का बनना लोगों को विशेष रूप से आश्चर्यचकित करता है। यह सभी आकृतियाँ प्राकृतिक रूप से बनी हुई मानी जाती हैं, जिन्हें किसी ने तराशा नहीं है।

शिवखोड़ी गुफा से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है, जो इस स्थान को और अधिक पवित्र बनाती है। इस कथा के अनुसार, भस्मासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने यह वरदान दे तो दिया, परंतु भस्मासुर की मंशा को पूरी तरह नहीं समझ पाए।

वरदान प्राप्त होते ही भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। वह शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। इस संकट से बचने के लिए भगवान शिव वहाँ से निकलकर पहाड़ियों की ओर भागे और एक गुफा में छिप गए। लोकमान्यता के अनुसार यही गुफा शिवखोड़ी गुफा थी।

भगवान शिव के छिप जाने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ किया और भस्मासुर भी उसका अनुकरण करने लगा। नृत्य के दौरान उसने अनजाने में अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और अपने ही वरदान से भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा हुई और शिवखोड़ी गुफा को उनका पवित्र निवास माना जाने लगा।

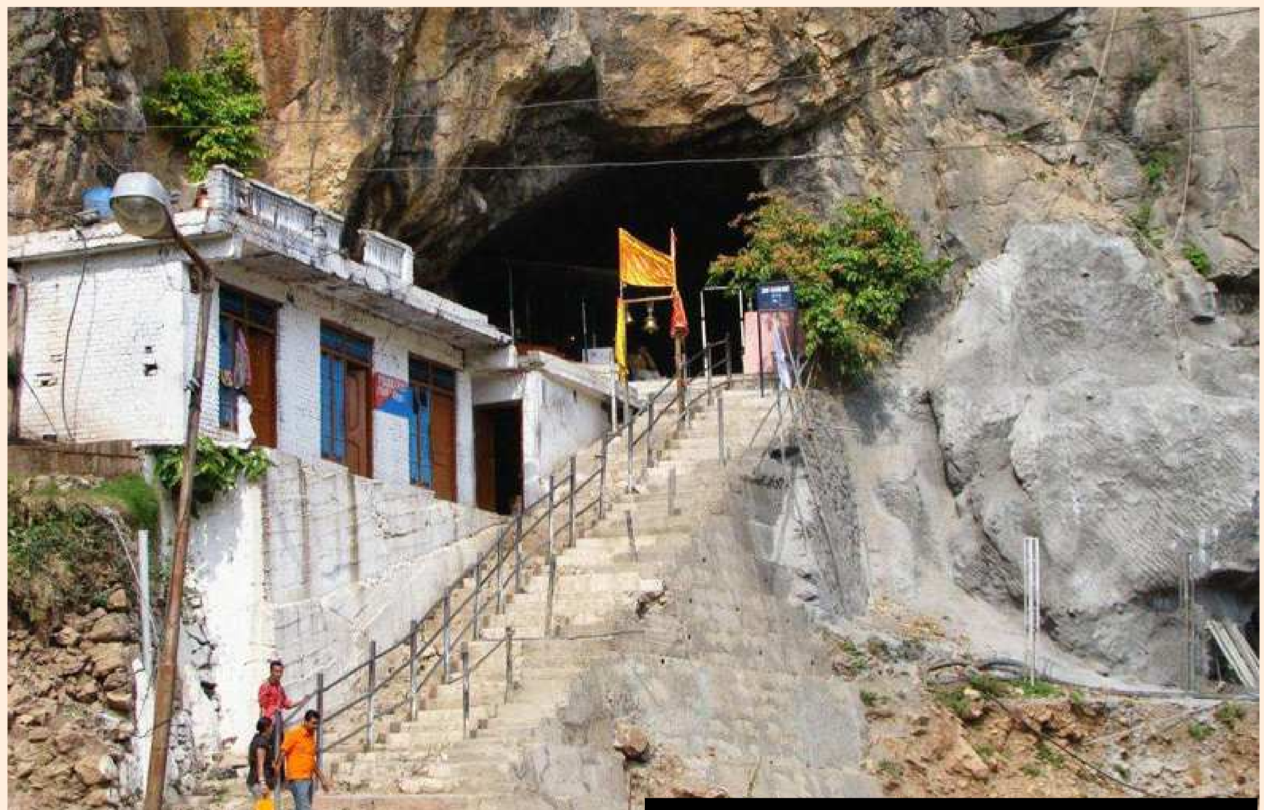

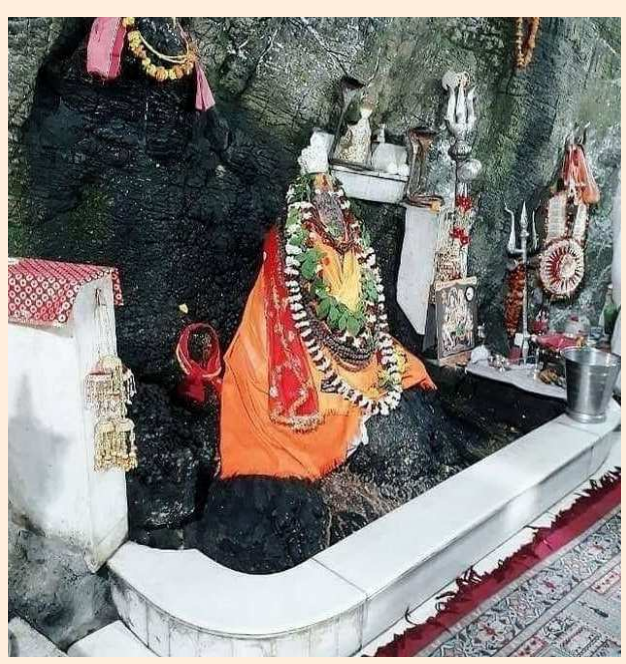

आज भी श्रद्धालु इस गुफा को भगवान शिव के चमत्कारी निवास स्थल के रूप में देखते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएँ भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं।

शिवखोड़ी गुफा केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह मानव आस्था, भय, श्रद्धा और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। यह स्थान यह दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक संरचनाएँ समय के साथ पौराणिक कथाओं और लो. कविश्वासों से जुड़कर आध्यात्मिक केंद्र बन जाती हैं। चाहे कोई इसे पौराणिक आस्था माने या प्राकृतिक रहस्य, शिवखोड़ी गुफा सदियों से लोगों के मन में भगवान शिव के दिव्य निवास के रूप में प्रतिष्ठित है।

इस प्रकार शिवखोड़ी गुफा की कथा केवल एक गुफा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आस्था की कहानी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है।

लेखक एक स्वतंत्र (फ्रीलांस) लेखक हैं और विभिन्न समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं

आज भी व्यापक रूप से यह मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिसे शास्त्रों और पुराणों में शिवलोक कहा गया है। इसके साथ ही जम्मूदृकश्मीर क्षेत्र से जुड़ा एक विशेष विश्वास भी है कि भगवान शिव का दिव्य निवास शिवखोड़ी गुफा में है। उधमपुर जिले के निकट स्थित यह गुफा अपनी रहस्यमय संरचना और आध्यात्मिक महत्ता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग विद्यमान है, जिसे किसी मानव ने नहीं बनाया। गुफा में नंदी, माता पार्वती और सर्पाकार आकृतियाँ भी प्राकृतिक रूप से बनी मानी जाती हैं। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार, भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है। शिवखोड़ी गुफा आस्था, श्रद्धा और रहस्य का जीवंत प्रतीक है।

‘राजनैतिक व्यंग्य-समागम’

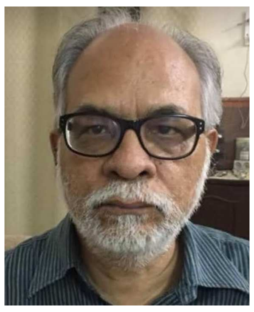

विष्णु नागर

’1. धर्मक्षेत्रे–कुरुक्षेत्रे : विष्णु नागर’

तो प्यारे देशवासियो, हमारा देश एक बहुत रोचक मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। भूल जाइए, अजट–बजट। बजट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लोग रोते हैं, सरकार हंसती रहती है। मंत्री और सत्तापक्ष के सांसद बजट के पक्ष में बेसुरा राग गाते रहते हैं और विपक्ष जोर–जोर से चीखता–चिल्लाता रहता है। इनमें से किसी को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गरजने–बरसने का आनंद उठाता है, तो कोई नाचने–गाने का! डेढ़–दो घंटे तक बजट पढ़ने से वित्त मंत्री के पैरों, जुबान और आंखों का मुफ्त परीक्षण हो जाता है। हैल्थ चेकअप हो जाता है।

बजट का यह स्थायी भाव है। जिसे सब पाज़िटिव दिखता है, समझो कि वह सत्ता में है और जिसे सब निगेटिव दिखता है, वह विपक्ष में है। सेठ दोनों तरफ़ होते हैं। उन्हें यह विशेष सुविधा है। उनका अपना फायदा–नुकसान ही देश का फायदा–नुकसान है। जब तक बजट रहेगा, यह सब रहेगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है और नया हो भी नहीं सकता। विपक्ष बजट की तारीफ़ नहीं कर सकता, सत्ता पक्ष उसकी निंदा नहीं कर सकता। इसलिए बजट को भूलो।

अभी बजट से अधिक रोचक है, धर्मक्षेत्रे– कुरुक्षेत्रे में चल रहा युद्ध! दोस्तो, कल तक जो श्बटेंगे तो कटेंगे श के नारे लगा रहे थे, वे खुद इन दिनों बंटे और कटे हुए से हैं। जो श्एक हैं तो सेफ हैंश का नारा बुलंद कर रहे थे, उनकी एकता इतनी अधिक ख़तरे में है कि उनकी हालत पर रोना आता है और मुश्किल यह है कि मेरे पास रूमाल नहीं है। बंटने–कटने की बातें जिनको केंद्र में रखकर कही जा रही थीं, वे फिलहाल केंद्र से बाहर हैं। लड़ वे रहे हैं, जो एक हो रहे थे।

एक मुख्यमंत्री, एक शंकराचार्य से भिड़ा हुआ है। उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है, तो शंकराचार्य, मुख्यमंत्री से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं! मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम शंकराचार्य नहीं, तो शंकराचार्य ने कहा तुम तो हिंदू भी नहीं! मुख्यमंत्री ने कहा, मैं तुम्हें

राजसी ठाठ–बाट के साथ माघ मेला में गंगा स्नान नहीं करने दूंगा। शंकराचार्य ने कहा कि अच्छा तो अब एक मुख्यमंत्री मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाणपत्र मांगेगा, उसकी ये हैसियत हो गई है? चालीस दिन देता हूं उसे, वह अपने को हिंदू साबित करे। नहीं किया, तो उसे हिंदू धर्म से बाहर करवा दूंगा! वह हिंदू रहना चाहता है, तो अपने राज्य में गो–हत्या बंद करवाए, वरना यह साबित हो जाएगा कि वह हिंदू नहीं, कालनेमि है, पाखंडी है, ढोंगी है। वह हिंदू है, तो गोमाता को राज्यमाता घोषित करे, वरना साधु–संत मिलकर उसे देख लेंगे! उधर कोई हिंदू रक्षा दल कह रहा है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये रावणाचार्य है, कांग्रेसाचार्य है।

लट्ठमलट्ठा हो रही है। हम जैसे दर्शकों को मज़ा आ रहा है। अभी तो दोनों की नाक इतनी ज्यादा ऊंची है कि गर्दन नीची होने पर भी नाक ऊंची ही रहती है! एक चाहता है दूसरा अपनी नाक पहले नीची करे, दूसरा कह रहा है कि नहीं करूंगा, पहले वह नीची करे।

बाहरी शरीर में वैसे नाक थोड़ा–सा स्थान घेरती है, मगर पुरुष की सारी इज्ज़त इस टुन्नी सी नाक में समाई रहती है। बिना कटे यह नाक कट जाती है और बिना जुड़े यह जुड़ जाती है। तो अब दोनों एक–दूसरे की नाक काटने पर तुले हैं और संघ ने चाहा, तो दोनों की नाक कटकर फिर जुड़ जाएगी, मगर अभी तो दोनों ओर से छुर्रियां तनी हुई हैं। दोनों वार के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। दोनों की हथेलियां एक–दूसरे की कटी हुई नाक रखकर दुनिया को दिखाना चाहती हैं। पिछले साढ़े ग्यारह साल का यह अपनी तरह का सबसे रोचक दृश्य है!

तो ये तो हिंदुत्व का एक मोर्चा है। एक और मोर्चा भी खुल चुका है और वह बंद होकर भी बंद नहीं होने वाला है! यूजीसी की नियमावली का झगड़ा तो सुप्रीम कोर्ट की कृपा से हिंदुत्ववादियों के पक्ष में अभी सुलझ गया है, मगर सुलझ कर भी गहरे घाव दे गया है और ये घाव ऐसे हैं कि मरहम कोई भी लगाओ, सूखने वाले नहीं हैं। यूपी में श्आई लव योगी जी, गो बैक यूजीसीश, श्योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहींश, श्तूने सवर्ण समाज की पीठ में छुरा भोंका है, हम तुझे छाती ठोंककर जवाब देंगेश, श्मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी, योगी जी की छाती मेंश के नारे लगे हैं।मोदी के पुतले को पीटा गया है, जलाया गया है। उनकी जाति याद दिलाई गई है और किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है!

मोदी जी की छाती में ये दर्द क्या अंदर तक घुसा नहीं है?मोदी जी की आदत किसी को माफ़ करने की नहीं है।इसके लिए वह योगी जी को कभी माफ कर सकते हैं?कभी नहीं! मोदी, योगी से बड़ा और पुराना घाघ है। ऊपर की चुप्पी अंदर की खलबली दिखा रही है। उधर योगी के बंदे कह रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, उधर मोदी बिना कहे कह रहे हैं, योगी अब तेरी भी खैर नहीं।

तो योगी जी ने दोनों मोर्चे खोल रखे हैं। घर की लड़ाई पहली बार सड़क पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस जंग पर ठंडा पानी डाला है, मगर चिनगारियां नीचे दबी हुई हैं। हिंदुत्व के सौ साला अभियान की यह गति होगी, महीने भर पहले तक यह कौन जानता था! इतनी जल्दी हिंदुत्व की सांस फूलने लगी है, इसका किसे पता था?इतनी जल्दी द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाएगा, किसे मालूम था!

लोहे पर चांदी और सोने की पालिश अब धीरे–धीरे उतरने लगी है। जो दूसरों को संकट में डाल रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, शस्त्र पूजन कर रहे थे, मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे थे, खुद संकट में आए हुए से लग रहे हैं। कम–से–कम इसका श्रीगणेश तो हो चुका है।

ये सब सत्ता के नशे में चूर हैं। विश्वगुरु जी और जगद्गुरु जी भिड़ रहे हैं।

ऐसे में असम के मुख्यमंत्री सरमा जी का बंगाली मुसलमानों वाला राग बेसुरा लग रहा है। जो दुश्मन को नष्ट करने चले थे, जो इतिहास मिटाने चले थे, आज खुद नष्ट होने–मिटने के कगार पर हैं। इनके श्अच्छे दिनश जाने को बेताब से हैं। अच्छा है कि इनमें दंगल मचा हुआ है। इनका सनातन में तनातनी का आलम है। अगर मैं ईश्वर को मानने वाला हुआ होता, तो कहता कि हे भगवान देश को हर रोज भटकाने वालों को इतना भटका कि ये घर का रास्ता ही भूल जाएं।

मगर सावधान, अभी विश्राम का समय आया नहीं है।

’(कई पुरस्कारों से सम्मानित विष्णु नागर साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार हैं। जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)’

’’’’’’’’’

’2. शुक्र है बापू, तुम ना हुए! रू राजेंद्र शर्मा’

एक तो 30 जनवरी की तारीख के बावजूद, तीस जनवरी वाली कोई बात नहीं थी। न मुकर्रर वक्त पर साइरन के जरिए पुकार और न जगह–जगह लाउडस्पीकरों से “दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल” की गुहारें।

उस पर सुबह–सुबह शांति वन पहुंच कर जो देखा, हैरान करने वाला था। बापू अपने चर्चित लंबे डग भरते हुए तेजी से वृक्षों के झुरमुट की ओर भागे से जा रहे थे।

दूर से ही उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा, इतनी सुबह उधर कहां अंधेरे की तरफ भागे जा रहे हैं और वह भी अपने पुजाने के दिन पर। साल में दो ही दिन तो आप को याद किए जाने के बचे हैं। दो अक्टूबर और तीस जनवरी। आज तो आपका नाम लेने वालों से लेकर, गोडसे का काम करने वालों तक, तमाम गद्दीधारी आपके ठिकाने पर आने वाले हैं और आज ही आप...।

बापू बिना रुके कदम बढ़ाते हुए बोले –– इसीलिए तो...! इससे पहले कि यह सालाना नाटक शुरू हो, मैं कहीं निकल जाना चाहता हूं। मुझे कम–से–कम इस पाखंड का हिस्सा नहीं बनना है।

पत्रकारीय उत्सुकता अब और जोर मारने लगी। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। यह कहते हुए पीछे–पीछे चलता रहा कि आप को अपनी पूजा कराने का शौक कभी नहीं था, यह तो सभी जानते हैं।

दिखावे की पूजा कराने का तो हर्गिज नहीं। फिर भी आप का यह मानना क्या अन्याय ही नहीं है कि राज करने वालों का आपकी मूर्ति पर/ तस्वीर पर फूल चढ़ाना, आपके आगे सिर झुकाना कोरा दिखावा ही है। संदेह का लाभ तो सभी को मिलना चाहिए। राज करने वाली पार्टी में सभी गोडसे भक्त थोड़े ही हैं। उनके यहां भी तो थोड़ी–बहुत वैराइटी तो होगी ही। हमें तो लगता है कि सच्चे गोडसे भक्त तो पहचान छुपाकर, जुबान चलाने वाले सोशल मीडिया हिंदू योद्धा ही ज्यादा हैं।

वर्ना मोदी जी तो दुनिया में जहां भी जाते हैं, खोजकर आपकी प्रतिमा पर शीष नवाते हैं। और आप हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में उन्हें मिल भी जाते हैं। फिर यह बहिष्कार...?

बापू समझ गए कि आसानी से उनका पीछा नहीं छूटने वाला है। रुक कर एक पेड़ के नीचे बने टूटे–फूटे चबूतरे पर बैठ गए। इशारा कर के मुझे भी बैठने का कहा।

फिर कहने लगे कि तुझे क्या लगता है कि मुझे इसकी परवाह है कि कौन वाकई मेरी पूजा करता है और कौन गोडसे की? और वह भी इसलिए कि गोडसे ने मेरे सीने पर तीन गोलियां दाग कर मेरी हत्या की थी? या मुझे इसकी परवाह है कि पिछले अठहत्तर साल में तीस जनवरी का दिन, शहादत या बलिदान दिवस से शुरू होकर, पहले पुण्यतिथि हुआ और अब सिर्फ जयंती या सालगिरह रह गया है? यहां तक कि अहिंसा दिवस, स्वच्छता दिवस, शराब. बंदी दिवस, आदि में से कुछ भी। मुझे गलत मत समझना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेशक, मुझे भी फर्क पड़ता है, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के तौर पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, देश के बापू के रूप में। मुझे फर्क पड़ता है, तो इसलिए कि इससे देश को फर्क पड़ता है।

मेरे चेहरे पर मेरा प्रश्न साफ लिखा था –– कैसे? बापू अपने लोकख्यात धीरज से हाथ पकड़ कर समझाने लगे। तू तो पत्रकार है, उत्तराखंड वाले ताजा किस्से का तो तुझे पता ही होगा। कहने को देवभूमि है और बड़ी तेजी से राक्षस–भूमि बनने की राह पर फिसल रही है। कोटद्वार में एक दुकान के नाम पट्ट पर लिखा है बाबा। पर उसका मालिक मुसलमान है। बस इसी का बहाना लेकर भगवाधारी झुंड बनाकर उसकी दुकान बंद कराने के लिए पहुंच गए। बाबा शब्द तो हमारा है। मुसलमान की दुकान का नाम बाबा नहीं रहने देंगे! लगे उपद्रव करने। पुलिस थी, पर हस्ब ए मामूल, तमाशा देखने की ड्यूटी पर। पर उनके तोड़–फोड़ कर पाने से पहले, दीपक नाम का एक पहलवान उनके और बाबा की दुकान के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। एलान कर दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और न दुकान को हाथ लगाने दूंगा और न दुकानदार को। भगवाधारी झुंड ऐसी धर्मनिरपेक्षतावादी रुकावट के लिए तैयार नहीं था, पीछे लौट गया। तमाशा खत्म, तो पुलिस भी घर चली गयी। पर धामी जी के राम राज्य में कहानी इतने पर खत्म कैसे हो जाती? अगले दिन भगवाई और बड़े झुंड में और पूरी तैयारी के साथ अपने धार्मिक यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षस, दीपक को निपटाने पहुंच गए। जी भरकर उन्हें और उनके परिवार को गालियां दीं और हंगामा किया। पुलिए एक बार फिर तमाशा देखती रही! अब जिन धामी जी की पुलिस के अशीर्वाद से आए दिन ऐसा ही कुछ न कुछ हो रहा है, वह तीस जनवरी को मुझे पूजने का स्वांग करें और मैं उनसे फूल चढ़वाऊं, अब बर्दाश्त नहीं होगा।

मैंने कहा, पर एक के लिए सब को...? बापू ने झिडक़ते हुए कहा, यह तो एक उदाहरण है। यहां तो पूरा का पूरा अवा ही बिगड़ा हुआ है। सुना नहीं, असम का हिमंता बिस्व सरमा किस के नाम पर चुनाव जीतना चाहता है। इसके नाम पर कि वह मियां लोग को इतना परेशान करेगा कि देश छोडक़र भाग जाएंगे! क्या मैं उससे श्रद्धा–सुमन चढ़वाऊं? या उत्तर प्रदेश वाले योगी से, जिसका चोला साधु का, गद्दी मुख्यमंत्री की और काम...। अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि आपरेशन लंगड़ा चलवाकर अगले ने आठ साल में 11 हजार लोगा. ` को पांव में गोली मार कर लंगड़ा कराया है। उससे अपनी अहिंसा का सम्मान कराऊं? या ओडिशा के मांझी से, जिसके राज में बंगालियों को बाकायदा मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है या पुलिस द्वारा जबरन बांग्लादेश में धकेला जा रहा है।

मैंने आखिरी दलील दी –– पर मोदी जी? अब बापू ने थोड़ा नाराजी से घूरा! इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? यह तो पूरे आस्तिकों का ब्रह्मांड है, जिसका सृष्टा, कर्ता, संचालक, सब एक है!

इसके बाद मैं क्या कहता? फिर भी उठते–उठते मैंने अपने हिसाब से चतुराई की सलाह दी। आपके गायब हो जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे आप के गायबाने में ये आप की जगह पर किसी और को बापू बनाकर बैठा देंगे, पर अपने कर्म–कांड और आचार–व्यवहार, दोनों में जरा–सा खलल नहीं पड़ने देंगे।

बापू उठकर लंबे डग भरकर पेड़ों के झुरमुट में अदृश्य होने की ओर बढ़ते चले गए –– पीछे आवाज सुनाई दी, इसीलिए तो मेरा इनसे दूर रहना और भी जरूरी है, अच्छा है!

’(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक है।)’

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नगरी हमले को लेकर लोगों में रोष, असली आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

सबका जम्मू कश्मीर

नगरी/कठुआ : कस्बा नगरी में 31 जनवरी की शाम हुए हमले का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक हमले के सभी असली आरोपी सामने नहीं आए हैं, जिससे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, नगरी पल्ली रोड पर पूर्व सैनिक, एक दुकानदार और एक महिला पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। हमले में नगरी पुल के पास स्थित एक दुकानदार भी घायल हुआ था। घटना के बाद रविवार को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि मामले से जुड़े सभी लोगों को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें एक युवक को 6 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सूत्रों की मानें तो पुलिस ने लोहे की पाइप और कुछ अन्य सामान बरामद करने की सूचना सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार, पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी आगे भी कुछ लोगों को निशाना बनाने की फिराक में था।

हालांकि स्थानीय लोग अब भी पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि हमले में इस्तेमाल हथियारों को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है और घायल लोग पूरी तरह से बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। लोगों की मांग है कि पुलिस घायल व्यक्तियों के बयान के बाद ही पूरे मामले का खुलासा करे और इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से इस घटना को लेकर चर्चा जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और शाम होते ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं।

अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मामले का पूरा सच सामने आएगा, ताकि क्षेत्र में सामान्य माहौल बहाल हो सके।

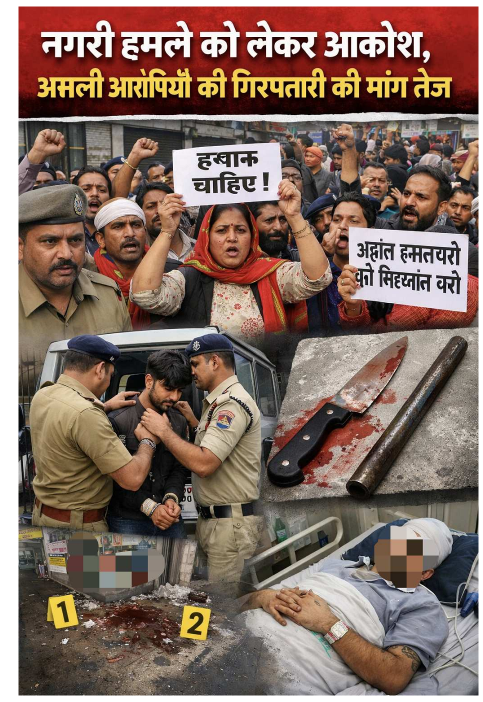

बड़े पैमाने पर निर्माण, सुनिश्चित परिणाम एकीकृत शासन व्यवस्था कैसे भारत की अवसंरचना यात्रा को नया आकार दे रही है

विनायक पई

पिछले एक दशक में भारत के अवसंरचना परिदृश्य में जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह केवल सड़कों, पुलों, बंदरगाहों या रेल लाइनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। यह बदलाव कहीं अधिक गहरा और संरचनात्मक है, जिसने नीति–निर्माण, शासन प्रणाली और क्रियान्वयन के पूरे ढांचे को नए सिरे से परिभाषित किया है। आज भारत जिस अवसंरचना युग में प्रवेश कर चुका है, उसकी पहचान केवल निवेश के विशाल पैमाने या निर्माण की तेज गति से नहीं होती, बल्कि उस एकीकृत, परिणाम आधारित शासन मॉडल से होती है, जो नीति की मंशा, केंद्रराज्य सहयोग और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को एक ही सूत्र में बांधता है।

वर्तमान चरण को पूर्ववर्ती अवसंरचना चक्रों से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब अवसंरचना को अलग–अलग परियोजनाओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है। भारत निर्णायक रूप से एक प्लेटफॉर्म आधारित शासन मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें योजना, अनुमोदन, क्रियान्वयन और निगरानी सभी एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा परिणाम यह है कि परियोजनाएं केवल शुरू ही नहीं होतीं, बल्कि समयबद्ध, अनुशासित और अपेक्षित परिणामों के साथ पूरी भी होती हैं।

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार को देखें तो यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष 2014 में जहां भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग इक्यानबे हजार किलोमीटर थी, वहीं वर्ष 2024 तक यह बढ़कर एक लाख छियालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई। यह वृद्धि मात्र आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है। इसके साथ ही निर्माण की गति में भी ऐतिहासिक सुधार हुआ है। जहां पहले प्रतिदिन औसतन बारह किलोमीटर सड़क निर्माण होता था, वहीं अब यह गति चौंतीस किलोमीटर प्रतिदिन से भी अधिक हो चुकी है।

अक्सर इस उपलब्धि को तकनीकी दक्षता या ठेकेदारी क्षमता के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह शासन प्रणाली की सफलता का परिणाम है। यह उस व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जिसमें परियोजनाओं से जुड़ी बाधाओं की पहचान पहले ही कर ली जाती है और उनके समाधान के लिए समय पर निर्णय लेने का अधिकार और तंत्र मौजूद होता है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, उपयोगिता स्थानांतरण और वित्तीय प्रवाह जैसे मुद्दे अब परियोजना को वर्षों तक रोकने वाले अवरोध नहीं रह गए हैं, बल्कि समन्वित प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाए जाते हैं।

सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से देखें तो तेज क्रियान्वयन का सीधा लाभ समाज को जल्दी मिलने लगता है। जब सड़कें समय पर बनती हैं, तो दूर–दराज के क्षेत्र बाजारों से जुड़ते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच आसान होती है, आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ती है और राष्ट्रीय सुरक्षा व लचीलापन मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त, बेहतर संपर्क और कम परिवहन समय उद्योगों के लिए लागत घटाता है, जिससे समग्र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

एकीकृत शासन, संस्थागत जवाबदेही और बहु–माध्यमीय योजना ने भारत की अवसंरचना को परियोजनाओं से आगे बढ़ाकर एक समन्वित, परिणामोन्मुख राष्ट्रीय प्रणाली में बदला है।

पिछले दशक की एक और निर्णायक विशेषता है समयबद्ध जवाबदेही का संस्थानीकरण। सक्रिय शासन और समय पर क्रियान्वयन कार्यक्रम, जिसे हिंदी में सक्रिय शासन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन मंच कहा जा सकता है, ने जटिल और बहु–मंत्रालयी परियोजनाओं के संचालन में एक नया मोड़ दिया। इस मंच के माध्यम से उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा होती है, जहां केवल प्रगति रिपोर्ट नहीं देखी जाती, बल्कि ठोस समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया जाता है।

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सांस्कृतिक है। अब देरी को सामान्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है और स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी तय की जाती है। जिन परियोजनाओं को पहले तकनीकी जटिलताओं या अंतर–मंत्रालयी समन्वय की कमी के कारण वर्षों तक लटका हुआ माना जाता था, वे अब अपेक्षाकृत अधिक पूर्वानुमेयता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही हैं। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है, बल्कि जनता और उद्योग जगत का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

इसी अवधि में सहकारी संघवाद की अवधारणा को भी अवसंरचना क्रियान्वयन के केंद्र में लाया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित, संरचित और उद्देश्यपूर्ण संवाद ने उन परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन का वातावरण पूरी तरह बदल दिया है, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। यह मॉडल संविधान में निहित भूमिकाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा सहमति बनाता है।

आज राज्य केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निष्क्रिय लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन और परिणाम प्रबंधन में सक्रिय साझेदार हैं। इससे न केवल निर्णय लेने की गति बढ़ी है, बल्कि कानूनी विवादों में भी कमी आई है और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन अधिक सुचारु हुआ है। उद्योग जगत के लिए यह पूर्वानुमेयता परियोजना जोखिम को कम करती है, जबकि नीति निर्माताओं के लिए यह भारत की संघीय वितरण क्षमता में विश्वास को और मजबूत करती है।

भारत की अवसंरचना रणनीति अब केवल संपर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में विकसित हो रही है। सड़कें अब अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक लॉजिस्टिक्स और गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुकी हैं। राजमार्गों को रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी परिवहन प्रणालियों से जोड़ने की योजना एकीकृत ढंग से बनाई जा रही है।

राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति जैसे ढांचे इस सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत की एक पुरानी संरचनात्मक समस्या, यानी उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, को कम करना है। नीति के स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि अवसंरचना की दक्षता केवल परिसंपत्तियों की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि उनके आपसी समन्वय से तय होती है। एकीकृत योजना न केवल दोहराव को कम करती है, बल्कि सार्वजनिक पूंजी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाती है।

स्पष्ट नीति संकेत, तेज निर्णय चक्र और जमीन पर दिखाई देने वाली प्रगति ने निवेशकों की धारणा को भी बदल दिया है। आज भारत में अवसंरचना को एक स्थिर और दीर्घकालिक निवेश अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसे संस्थागत निरंतरता और प्रशासनिक संकल्प का समर्थन प्राप्त है। निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह वातावरण तकनीक, यंत्रीकरण, सुरक्षा प्रणालियों और कौशल विकास में दीर्घकालिक निवेश को संभव बनाता है। अब कंपनियां अनिश्चितता के लिए तैयारी करने के बजाय आत्मविश्वास के साथ विस्तार की योजना बना सकती हैं।

जैसे–जैसे भारत अवसंरचना विस्तार के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, नीति प्राथमिकताओं में भी बदलाव की आवश्यकता है। अब जोर केवल मात्रा पर नहीं, बल्कि मूल्य पर होना चाहिए। परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण में बेहतर योजना और उच्च गुणवत्ता वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। परियोजना के पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी, जिसमें स्थिरता और लचीलापन डिजाइन से लेकर संचालन तक शामिल हों।

डिजिटल शासन और डेटा एकीकरण के माध्यम से निर्णय लेने की समयसीमा को और संक्षिप्त किया जा सकता है। राज्यों और स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि तकनीक के उपयोग से क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। जोखिम साझा करने की ऐसी रूपरेखाएं विकसित करनी होंगी, जो गति और वित्तीय विवेक के बीच संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही, अवसंरचना जीवन चक्र के हर चरण में कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

आज भारत की अवसंरचना यात्रा न तो नीयत की कमी से बाधित है और न ही क्षमता की कमी से। चुनौती अब इन प्रणालियों को और गहराई देने, संस्थागत निरंतरता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की है कि अवसंरचना समावेशी, प्रतिस्पर्धी और लचीले विकास की मजबूत नींव बनी रहे। जिस तरह से एकीकृत शासन, स्पष्ट जवाबदेही और बहु–माध्यमीय योजना ने पिछले दशक में भारत की दिशा बदली है, उसी तरह आने वाले वर्षों में यह देश को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

(लेखक भारतीय उद्योग परिसंघ, महाराष्ट्र के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सड़क एवं राजमार्ग समिति के अध्यक्ष हैं)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
संपादकीय

परमाणु संतुलन संकट

संपादक – राज कुमार

शांति की किसी भी स्थायी व्यवस्था की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य में यही विश्वास सबसे अधिक कमजोर दिखाई देता है। ऐसे समय में न्यू स्टार्ट (न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी) जैसी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि का समाप्त होना दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या और तैनाती को सीमित करने का एकमात्र कानूनी ढांचा थी। इसके समाप्त होने से न केवल रणनीतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ा है, बल्कि एक नई और अधिक खतरनाक परमाणु हथियार दौड़ की आशंका भी गहरा गई है। न्यू स्टार्ट संधि 8 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी और इसने अमेरिका तथा रूस के परमाणु हथियार भंडार को नियंत्रित किया। ये दोनों देश मिलकर दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत परमाणु हथियार रखते हैं। अनुमान के अनुसार, दोनों के पास पाँच हजार से अधिक परमाणु वारहेड हैं। इनके बाद चीन का स्थान आता है, जिसके पास लगभग 600 परमाणु हथियार माने जाते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के पास क्रमशः लगभग 180 और 170 परमाणु हथियार हैं। न्यू स्टार्ट ने तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड की सीमा 1,550 तय की थी और निरीक्षण, सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा डेटा साझा करने की एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की थी। यह संधि परमाणु हथियारों की दौड़ को समाप्त नहीं करती थी, लेकिन उसे नियंत्रित अवश्य करती थी। इससे अनिश्चितता और अंदाजों की गुंजाइश कम होती थी, जो अक्सर भय और अविश्वास को जन्म देती है। भय ही हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा ईंधन होता हैकृपीछे छूट जाने का डर, अचानक हमले का डर और अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना। न्यू स्टार्ट ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उन्हें प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण झूठे अलार्म और गलत आकलन से होने वाली विनाशकारी स्थितियों की संभावना भी कम हो जाती थी। आज स्थिति कहीं अधिक जटिल है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अमेरिका–चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे माहौल में न्यू स्टार्ट का समाप्त होना खतरनाक संकेत देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि को "खराब तरीके से बातचीत की गई" बताते हुए एक नई, आधुनिक और बेहतर संधि की वकालत की थी, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। तर्क में कुछ दम जरूर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन फिलहाल ऐसी किसी त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका परमाणु भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है और वह तेजी से अपने सैन्य ढांचे का विस्तार कर रहा है। चीन का कहना है कि जब तक अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों में भारी कटौती कर उसके स्तर के करीब नहीं आते, तब तक वह किसी समझौते में शामिल नहीं होगा। दूसरी ओर, रूस ने न्यू स्टार्ट के समाप्त होने से पहले ही निरीक्षण और डेटा साझा करने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। तकनीकी स्तर पर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। हथियार नियंत्रण के लिए जटिल सत्यापन नियम, गिनती की पद्धतियाँ और गहन निरीक्षण की जरूरत होती है, जिन्हें तय करने में वर्षों लग जाते हैं। इसके अलावा, आज कई ऐसे हथियार हैं जो किसी भी समझौते के दायरे में नहीं आते, जैसे सामरिक परमाणु हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें और दोहरे उपयोग वाली प्रणालियाँ। ये सभी स्थिति को और अस्थिर बनाती हैं। ऐसे में सबसे व्यावहारिक रास्ता यही है कि अमेरिका और रूस कम से कम न्यू स्टार्ट की मूल सीमाओं का पालन करते रहें और निरीक्षण व्यवस्था को बहाल करें, जब तक कि कोई नई संधि अस्तित्व में नहीं आती। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दुनिया एक बार फिर अनियंत्रित परमाणु हथियार दौड़ की ओर बढ़ सकती है, जिसके परिणाम मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।

प्रकृति की नाराजगी को नहीं समझा तो मानव अस्तित्व खतरे में

ललित गर्ग

प्रकृति अपनी उदारता में जितनी समृद्ध है, अपनी प्रतिशोधी प्रवृत्ति में उतनी ही कठोर है। जब तक मनुष्य उसके साथ तालमेल में रहता है, तब तक वह जीवन को वरदान देती है, जल, जंगल और जमीन के रूप में। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं और तथाकथित आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति की उपेक्षा करने लगता है, यही प्रकृति विनाश का रूप धारण कर लेती है। आज पूरे भारत में जो बाढ़, जल प्रलय और मौसम के अनियंत्रित बदलाव के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे केवल प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि हमारी गलतियों का सीधा परिणाम हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप के पीछे महज संयोग या 'कुदरत की नाराज़गी' को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। यह आपदाएं सीधे–सीधे जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित विकास मॉडल का परिणाम हैं। पहाड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है, लेकिन नीतिनिर्माताओं ने पहाड़ों के विकास को मैदानी मॉडल पर ढालने की कोशिश की। बड़े–बड़े होटल, अव्यवस्थित सड़कें, बांध, खनन और निर्माण ने पहाड़ों की नाजुक संरचना को हिला दिया। जब जंगल काटे जाते हैं तो वर्षा का पानी भूमि में समाने के बजाय सीधे तेज धाराओं के रूप में बहने लगता है। यही बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कारण बनता है, इसी से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, देश के बड़े हिस्से में जन–जीवन अस्त–व्यस्त है, लाखों हेक्टेयर फसलें जनमग्न है, जान–माल का नुकसान भी बड़ा हुआ है, भारी आर्थिक नुकसान ने घना अंधेरा बिखेर दिया है। चारों ओर चिन्ताओं एवं परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं।

आज की बाढ़ और जल प्रलय केवल पानी का उफान नहीं, बल्कि हमारी गलतियों का आईना है। यह प्रकृति का प्रतिशोध है, उसकी चेतावनी है कि यदि अब भी नहीं चेते तो भविष्य और भी विकराल होगा। महात्मा गांधी ने कहा था–"प्रकृति हर किसी की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं।" यही सच्चाई है। यदि हमने संतुलन नहीं सीखा, तो यह विनाशकारी दृश्य आने वाले वर्षों में और भयावह होंगे। लेकिन यदि हमने चेतावनी को अवसर माना, तो प्रकृति फिर से मां की तरह हमें संभाल लेगी। जीवनदायी पानी जब अपने विकराल रूप में सामने आता है तो उसका प्रकोप कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है, यह इस वर्ष की मूसलाधार मानसूनी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। सामान्यतः जल जीवन का आधार है, लेकिन जब वही जल अपनी मर्यादा तोड़कर प्रलयंकारी रूप में आता है तो घर, खेत, सड़क, पुल, मंदिर–मस्जिद और मानवीय जीवन तक बहाकर ले जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य इस समय प्रकृति के ऐसे ही कहर का दंश झेल रहे हैं। बादल फटने की अप्रत्याशित घटनाएं, पहाड़ों से टूटते हिमखंड, अचानक बहते मलबे और बेकाबू नदियों का सैलाब–ये सब मिलकर भयावह परिदृश्य खड़ा कर

रहे हैं। वनों की कटाई ने न केवल भूमि की जलधारण क्षमता घटाई है, बल्कि स्थानीय जलवायु चक्र को भी प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ा है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अप्रत्याशित समय पर अत्यधिक वर्षा हो रही है। यही कारण है कि बादल फटने जैसी घटनाएं पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई हैं। पहाड़ों की बस्तियां, जो कभी प्राकृतिक संतुलन में जीती थीं, अब मानवजनित गतिविधियों की मार झेल रही हैं। दरअसल, समस्या का मूल यह है कि हमने विकास की परिभाषा को केवल कंक्रीट और मशीनों से जोड़ दिया है। पर्यावरणीय संतुलन और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को दरकिनार कर योजनाएं बनाई गईं। इसी का परिणाम है कि जब आपदा आती है तो न तो हमारी चेतावनी प्रणाली पर्याप्त साबित होती है और न ही प्रशासन की तैयारियां। सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि अब तक अपनाए गए उपाय अपर्याप्त हैं। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि समस्या कितनी गंभीर है।

भारत की नदियाँ कभी जीवन का स्रोत मानी जाती थीं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के किनारे सभ्यताएँ पली–बढ़ीं। लेकिन आज वही नदियाँ मौत का पैगाम बनकर आती हैं। कारण है उनके प्राकृतिक प्रवाह में मानवीय हस्तक्षेप–बेतरतीब बांध, अतिक्रमण, नालों में बदल चुकी धारा और किनारों पर बसी बस्तियाँ। भारत में हर साल औसतन 1,600 लोग बाढ़ से मारे जाते हैं और लगभग 75 लाख लोग प्रभावित होते हैं। फसलें तबाह होती हैं, पशुधन मरता है और अरबों रुपए की आर्थिक क्षति होती है। केवल 2023 में उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली में आई बाढ़ से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों में मौसम का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ चुका है। मानसून जो पहले जून से सितंबर तक नियमित हुआ करता था, अब अनिश्चित और असमान हो गया है। कभी 24 घंटे में महीनों की बारिश हो जाती है, तो कभी लंबे सूखे का दौर देखने को मिलता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण की पोल खोल दी। 2023 में दिल्ली में यमुना का 45 साल का रिकॉर्ड टूटना इस बात का संकेत है कि शहर जलवायु परिवर्तन और अव्यवस्थित शहरीकरण के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं।

देश के लगभग हर हिस्से में जल प्रलय की कहानियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन से गांव उजड़ रहे हैं। बिहार और असम में बाढ़ हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती है। दिल्ली और मुंबई जैसे आधुनिक महानगर भी जलजमाव से पंगु हो जाते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में भी अनियंत्रित बारिश और बाढ़ का नया खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर नावें चल रही हैं, पुल बह गए हैं, खेत–खलिहान जलमग्न हैं। यह नजारा केवल विनाश का नहीं, बल्कि हमारी नासमझी का प्रमाण है। प्रकृति बार–बार संकेत देती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है, लेकिन हमने उसकी सीमाओं को लांघ दिया है। पहाड़ों को खोखला कर सुरंगें और सड़कें बनाई गईं। जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। नदियों को उनके मार्ग से हटाकर कृत्रिम रास्तों में बांध दिया गया। आज जब बादल फटते हैं या नदियाँ बेकाबू होती हैं, तो यह केवल आपदा नहीं बल्कि प्रकृति का प्रतिशोध है। अब सवाल यह है कि इस संकट से निपटें कैसे। केवल राहत और मुआवजा देना समाधान नहीं है। आवश्यकता है दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने की। हमें जंगल बचाने होंगे, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना होगा, शहरी योजनाओं में जलनिकासी और हरियाली को महत्व देना होगा, पर्वतीय विकास में संयम लाना होगा और सबसे बढ़कर जनजागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग समझ सकें कि पर्यावरण की रक्षा ही उनके जीवन की रक्षा है। जरूरत है कि आपदाओं को केवल 'प्राकृतिक' न मानकर उन्हें 'मानव निर्मित' एवं सरकार की गलत नीतियों की आपदाएं' भी समझा जाए। इसका अर्थ है कि इनका समाधान केवल राहत और बचाव तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक रणनीति से जुड़ा होना चाहिए। विशेषज्ञों की राय, वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय समुदायों के अनुभवों को मिलाकर ऐसी नीतियां बननी चाहिएं, जो पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखें। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने समय रहते संतुलित विकास का मार्ग नहीं चुना तो भविष्य और अधिक भयावह होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना, पहाड़ी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना, आपदा प्रबंधन तंत्र को त्वरित और प्रभावी बनाना, और सबसे बढ़कर–वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, यह सब आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली भारी जन–धन हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

इस वर्ष की बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं केवल त्रासदी नहीं, बल्कि एक

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

प्रगति@50 : जब मंशा नहीं, बल्कि डिलीवरी शासन की परिभाषा बनती है

टी.के. रामचंद्रन

प्रगति/50 यह दर्शाता है कि समन्वित निर्णय, शीर्ष नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी और तकनीक आधारित निगरानी से ही शासन में वास्तविक परिणाम और भरोसा पैदा होता है।

भारत सरकार की दो दूरगामी और परिवर्तनकारी पहलों – प्रधानमंत्री गति शक्ति और प्रगतिकृने देश में बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की सोच को गहराई से प्रभावित किया है। इन दोनों में से जहाँ प्रधानमंत्री गति शक्ति अवसंरचना नियोजन के लिए एक समग्र ढाँचा प्रस्तुत करती है, वहीं प्रगति यानी सक्रिय शासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन एक ऐसा मंच है, जिसने शासन की आत्मा को ही नई दिशा दी है। प्रगति के अंतर्गत आयोजित 50वीं उच्च–स्तरीय समीक्षा भारतीय राज्य के प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन को रेखांकित करती है। यह परिवर्तन मंशा से परिणाम की ओर, प्रक्रिया–पालन से प्रभाव की ओर और बिखरे हुए अधिकारों से समन्वित, समयबद्ध निष्पादन की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

प्रगति को केवल एक प्रशासनिक नवाचार के रूप में देखना इसकी भूमिका को कम करके आंकना होगा। वास्तव में यह शासन संरचना की एक सोची–समझी पुनर्रचना है, जिसका उद्देश्य वर्षों से चली आ रही उन कमजोरियों को दूर करना है, जिनके कारण नीतियाँ तो बनती रहीं, बजट स्वीकृत होते रहे, लेकिन ज़मीन पर परिणाम देर से या कभी–कभी बिल्कुल नहीं दिखे। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब अनेक समीक्षा तंत्र और निगरानी प्रणालियाँ पहले से मौजूद थीं, तब प्रगति कैसे सफल हुई और अन्य क्यों नहीं।

इसका उत्तर सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी की मूल प्रकृति को समझने में निहित है। भारत में परियोजनाओं में देरी लगभग एक स्वीकृत सच्चाई बन चुकी है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि देरी का कारण नीति की अस्पष्टता या वित्तीय संसाधनों की कमी है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अधिकांश मामलों में नीतियाँ स्पष्ट होती हैं और धन भी स्वीकृत होता है। समस्या शासन के खंडित स्वरूप से उत्पन्न होती है। मंत्रालय अपने–अपने दायरे में ऊर्ध्वाधर ढंग से कार्य करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हैं, न कि समानांतर रूप से। विवाद ऐसे चक्रों में फँस जाते हैं, जहाँ उन्हें सुलझाने का अधिकार किसी एक मंच के पास नहीं होता। गतिविधियाँ बढ़ती जाती हैं, परंतु जवाबदेही धीरे–धीरे बिखर जाती है।

इस खंडित व्यवस्था का सीधा प्रभाव यह होता है कि परियोजना–डिलीवरी का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाता है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय या वन स्वीकृतियाँ, नियामकीय अनुमोदन, संविदात्मक विवाद और अंतर–राज्यीय समन्वय जैसी समस्याओं के कारण अनेक परियोजनाएँ वर्षों तक अटकी रहती हैं। बहु–मंत्रालयी और बहु–राज्यीय राजनीतिक–अर्थव्यवस्था में, जहाँ हर इकाई अपने अधिकार–क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखती है, किसी एक के लिए दूसरे को सहमत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में पारंपरिक तरीका अपनाया जाता रहा हैकृलगातार बैठकें, चर्चाएँ, फील्ड विज़िट, समितियों का गठन और अंतहीन पत्राचार। यह तरीका धीरे–धीरे अप्रभावी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें चर्चा को निर्णय, गतिविधि को कार्य, आवागमन को प्रगति और केवल मंशा को उपलब्धि समझ लिया गया। नतीजतन, परियोजनाएँ आगे बढ़ने के बजाय प्रक्रियाओं में उलझती चली गईं।

यहीं से प्रगति का वास्तविक महत्व सामने आता है। प्रगति इन दीर्घकालिक संरचनात्मक विफलताओं का समाधान निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः डिज़ाइन करके करता है। यह एक प्रणाली–संयोजक के रूप में कार्य करता है, जो मंत्रालयों, राज्यों और ज़िलों के निर्णयकर्ताओं को एक साझा संस्थागत और डिजिटल मंच पर लाता है। इससे फाइलों की आवाजाही, अधिकार–क्षेत्र की अस्पष्टता और विभागों के बीच पत्राचार से होने वाली देरी सिमट जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रगति निष्पादन का एक विहंगम दृष्टिकोण बहाल करता है, जिससे नेतृत्व यह समझ पाता है कि प्रणाली वास्तव में कहाँ बाधित है, न कि केवल यह कि कोई फाइल किस मेज़ पर रुकी हुई है।

प्रगति की प्रभावशीलता में माननीय प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय है। उनकी अध्यक्षता में होने वाली समीक्षाएँ यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि डिलीवरी अब केवल एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि निष्पादन में विफलताओं पर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में दृढ़ता आती है और समीक्षा एक बाध्यकारी परिणाम–ढाँचे में बदल जाती है। इन बैठकों में लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, उनके लिए समय–सीमा निर्धारित होती है और उन्हें डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है, जिससे जवाबदेही स्पष्ट और लागू करने योग्य बनती है।

इस पूरे ढाँचे में तकनीक एक निर्णायक सहायक की भूमिका निभाती है। वास्तविक समय का डेटा, भू–स्थानिक दृश्यांकन और मैदानी अधिकारियों के साथ लाइव संवाद सूचना की असमानता को समाप्त करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय अनुमान या अधूरी जानकारी पर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों पर आधारित हों। महत्वपूर्ण यह है कि तकनीक प्रशासनिक विवेक को प्रतिस्थापित नहीं करती, बल्कि उसे सशक्त बनाती है और नेतृत्व की जिम्मेदारी को और मजबूत करती है।

प्रगति को पूर्ववर्ती समीक्षा तंत्रों से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका समापन पर जोर है। मुद्दे तब तक खुले रहते हैं, जब तक उनका समाधान न हो जाए। उनकी निरंतर निगरानी कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। अब स्पष्टीकरण या कारण परिणाम का विकल्प नहीं बन सकते। समय के साथ इस अनुशासन ने प्रशासनिक व्यवहार को बदल दिया है। मंत्रालय और राज्य अब समस्याओं को ऊपर पहुँचने से पहले ही सुलझाने की प्रवृत्ति अपनाने लगे हैं।

प्रगति के परिणाम स्पष्ट, दृश्य और मापनीय हैं। 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं में तेज़ी आई है। हाल के वर्षों में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दस परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति के अंतर्गत की गई, जिससे अवरोधों का समय रहते समाधान और निष्पादन में गति संभव हो सकी। इनमें से दो परियोजनाएँ इस मॉडल की प्रभावशीलता को विशेष रूप से रेखांकित करती हैं।

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एक अत्यंत व्यापक परियोजना है, जिसमें केंद्र सरकार के संस्कृति, रक्षा, विदेश, रेल और राजमार्ग जैसे कई मंत्रालयों के साथ गुजरात सरकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तटीय राज्यों के पवेलियन स्थापित किए जाने के कारण अन्य राज्य भी इसके भागीदार हैं। जब इस परियोजना को प्रगति के एजेंडा में शामिल किया गया, तो विभिन्न स्तरों पर तुरंत कार्रवाई तेज़ हो गई। आम तौर पर प्रगति की बैठक का एजेंडा कुछ महीने पहले ही अधिसूचित कर दिया जाता है, जिससे सभी हितधारकों में तात्कालिकता की भावना पैदा होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो मुद्दे अधिकारी या मंत्रालयी स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं, वे पहले ही सुलझ जाते हैं और केवल वे जटिल विषय समीक्षा बैठक में आते हैं, जिनके लिए शीर्ष स्तर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार जल मार्ग विकास परियोजना, जो राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, की प्रगति के अंतर्गत दो बार समीक्षा की गई। आज यह परियोजना अपने समापन चरण में है और इसके अधिकांश लंबित मुद्दों का समाधान हो चुका है।

प्रगति एक महत्वपूर्ण सत्य को रेखांकित करता है कि सार्वजनिक मूल्य केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब स्वीकृत निवेश वास्तविक परिणामों में बदलते हैं। अटकी हुई परियोजनाएँ इसलिए आगे बढ़ीं, क्योंकि नीतियों को फिर से नहीं लिखा गया, बल्कि निष्पादन के मार्ग सरल किए गए और जवाबदेही को सख्ती से लागू किया गया। उतना ही महत्वपूर्ण है सहकारी संघवाद में प्रगति का योगदान। मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों को एक ही वास्तविक समय के मंच पर लाकर यह खंडित जिम्मेदारी को साझा स्वामित्व में बदल देता है। केंद्र और राज्य अब अलग–अलग नहीं, बल्कि एक साथ परिणामों के लिए उत्तरदायी बनते हैं। प्रगति/50 इस बात का सशक्त प्रमाण है कि शासन के परिणाम संस्थागत डिज़ाइन पर निर्भर करते हैं। साइलो को तोड़कर, निष्पादन का विहंगम दृष्टिकोण बहाल करके और समापन को प्राथमिकता देकर प्रगति यह दिखाता है कि प्रभावी शासन का अर्थ केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि जो पहले से स्वीकृत है उसे तेज़, बेहतर और मिलकर पूरा करना है। समयबद्ध निष्पादन सेवाओं तक पहुँच को तेज़ करता है, अर्थव्यवस्था को गति देता है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है और राज्य की शासन–क्षमता में जनविश्वास को मजबूत करता है।

प्रगति नेतृत्व–प्रेरित डिलीवरी का एक सजीव अभिलेख भी है और जटिल शासन के लिए एक व्यावहारिक खाका भी। इसे मिल रहा वैश्विक ध्यान और सराहना इस बात का प्रमाण है कि जब शासन की परिभाषा मंशा से आगे बढ़कर डिलीवरी बन जाती है, तब परिणाम स्वयं बोलने लगते हैं।

(लेखक : पूर्व सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय)

वड्डा घल्लूघारा : विनाश से पुनर्जागरण की गाथा

वड्डा घल्लूघारा सिख इतिहास का वह भीषण अध्याय है, जहाँ विनाश, बलिदान और असहनीय पीड़ा के बीच भी समुदाय की सामूहिक चेतना और पुनर्जागरण की शक्ति जीवित रही।

रविंदर कौर राठौर

वड्डा घल्लूघारा सिख इतिहास के सबसे अंधकारमय और पीड़ादायक दिनों में से एक के रूप में स्मरण किया जाता है। इसे "महान सिख नरसंहार" कहा जाता है, क्योंकि इस घटना में न केवल असंख्य जानें गईं, बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व को मिटाने का सुनियोजित प्रयास किया गया। यह घटना केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि निर्दोष स्त्री–पुरुषों, बच्चों और वृद्धों पर किया गया वह क्रूर आक्रमण था, जिसने सिख समाज की सामूहिक स्मृति पर अमिट घाव छोड़े।

यह भयावह घटना 5 फ़रवरी 1762 ई० को घटित हुई। उस समय पंजाब का क्षेत्र निरंतर राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमणों और सत्ता संघर्षों से गुजर रहा था। अफ़ग़ान शासक अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, पहले भी भारत पर कई आक्रमण कर चुका था। सिख समुदाय उसके लिए एक उभरती हुई शक्ति था, जो न केवल सैन्य रूप से, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी स्वतंत्र पहचान स्थापित कर रहा था। यही कारण था कि दुर्रानी की दृष्टि में सिखों का अस्तित्व ही एक चुनौती बन गया था।

वड्डा घल्लूघारा के समय जिस सिख समूह पर आक्रमण हुआ, वह कोई संगठित सेना नहीं थी। वह एक चलता–फिरता समुदाय था, जिसमें परिवार अपने बच्चों, स्त्रियों और बुजुर्गों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। यह कारवां वर्तमान पंजाब के कुप रहिरा क्षेत्र के निकट पहुँचा था। सिखों का उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना था। वे अपने धार्मिक विश्वास, सामाजिक एकता और परंपराओं को बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे।

अहमद शाह दुर्रानी की सेना ने इस कारवां को चारों ओर से घेर लिया। उसके पास घुड़सवार सेना, भारी हथियार और तोपखाना था। सिखों के पास न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही युद्ध की तैयारी। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवारों की रक्षा के लिए साहसपूर्वक प्रतिरोध करने का प्रयास किया। परंतु सैन्य शक्ति के असंतुलन के सामने यह प्रतिरोध टिक नहीं सका।

जो कुछ हुआ, वह मानव इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक था। अनुमान के अनुसार लगभग बीस हज़ार से तीस हज़ार सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई। हज़ारों को बंदी बना लिया गया। अनेक परिवार एक ही झटके में समाप्त हो गए। माताएँ अपने बच्चों को खो बैठीं, पति–पत्नी अलग कर दिए गए, और बुजुर्गों को बिना किसी दया के मार डाला गया। चारों ओर केवल चीख–पुकार, रक्त और मृत्यु का दृश्य था।

इस भीषण त्रासदी को "वड्डा घल्लूघारा" कहा गया, ताकि इसे सन् 1746 ई० में हुए "छोटा घल्लूघारा" से अलग पहचाना जा सके। छोटा घल्लूघारा भी सिखों के विरुद्ध एक बड़ा नरसंहार था, परंतु 1762 का यह हत्याकांड उससे कहीं अधिक व्यापक और विनाशक. ारी था। यह केवल संख्या का अंतर नहीं था, बल्कि इसके पीछे की मंशा भी कहीं अधिक भयावह थीकृपूरे सिख समुदाय को जड़ से समाप्त कर देना।

इतिहास में इस घटना को विशेष रूप से इसलिए भी याद किया जाता है कि इसके बाद सिख समाज का क्या हुआ। सामान्यतः ऐसी त्रासदियों के बाद समुदाय बिखर जाते हैं, अपनी पहचान खो बैठते हैं या इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाते हैं। परंतु सिखों के साथ ऐसा नहीं हुआ। निरंतर उत्पीड़न, बार–बार के आक्रमणों और इस भीषण नरसंहार के बावजूद सिख समुदाय ने आत्मसमर्पण नहीं किया।

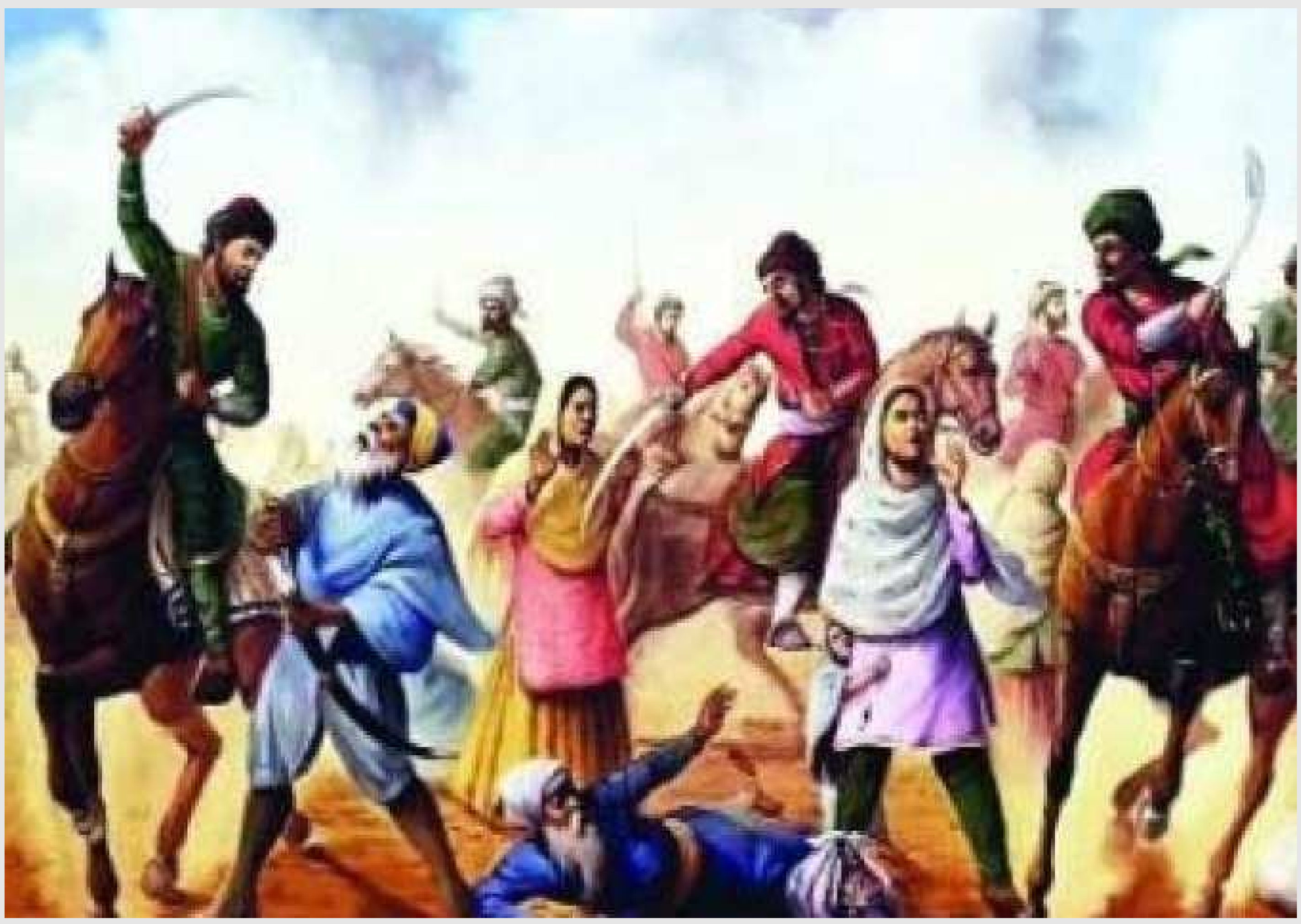

वड्डा घल्लूघारा सिख इतिहास की सबसे भीषण और पीड़ादायक त्रासदियों में से एक है, जिसे "महान सिख नरसंहार" कहा जाता है। 5 फ़रवरी 1762 ई. को अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब के कुप रहिरा क्षेत्र के पास एक चलायमान सिख समुदाय पर अचानक हमला किया। यह कोई संगठित सेना नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों से भरा काफ़िला था, जो सुरक्षित स्थान की तलाश में था। इस हमले में लगभग 20द्द30 हज़ार सिखों की हत्या हुई और हज़ारों बंदी बना लिए गए। इसका उद्देश्य सिख अस्तित्व को मिटाना था, परंतु परिणाम इसके विपरीत निकला। इस भीषण विनाश के बाद भी सिख समुदाय टूटा नहीं, बल्कि पुनर्गठित होकर आगे बढ़ा और आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सत्ता की नींव रखी। यह घटना शोक के साथ-साथ अदम्य साहस और पुनर्जागरण की प्रतीक है।

वड्डा घल्लूघारा के बाद के वर्षों में सिखों ने स्वयं को पुनर्गठित किया। उन्होंने अपनी मिसलों को फिर से संगठित किया, आपसी एकता को मजबूत किया और धीरे–धीरे अपनी राजनीतिक व सैन्य शक्ति को पुनः खड़ा किया। यह पुनर्जागरण किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस समुदाय को लगभग समाप्त मान लिया गया था, वही कुछ दशकों में पंजाब की निर्णायक शक्ति बन गया।

इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अंततः महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की स्थापना की ओर ले गई। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एक सशक्त और संगठित राज्य बनाया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य अनुशासन की मिसाल भी प्रस्तुत की। इस प्रकार, वड्डा घल्लूघारा में सिखों को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, वही उनके राजनीतिक उत्थान की पृष्ठभूमि बन गया। सिख परंपरा में शहादत का विशेष स्थान है। गुरु अर्जन देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक, और बाद में असंख्य ज्ञात–अज्ञात शहीदों तक, बलिदान सिख चेतना का अभिन्न अंग रहा है। वड्डा घल्लूघारा इसी परंपरा का एक अत्यंत पीड़ादायक, किंतु निर्णायक अध्याय है। यह घटना सिखों को यह स्मरण कराती है कि उनका अस्तित्व केवल भौतिक शक्ति पर नहीं, बल्कि नैतिक साहस, सामूहिक स्मृति और आध्यात्मिक दृढ़ता पर टिका है।

5 फ़रवरी 1762 ई० को सिख इतिहास में केवल शोक का दिन नहीं माना जाता, बल्कि यह आत्मचिंतन और संकल्प का भी दिन है। यह दिन यह सिखाता है कि जीवित रहना स्वयं में प्रतिरोध का एक रूप हो सकता है। जब किसी समुदाय को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया जाए और वह फिर भी स्वयं को पुनः खड़ा कर ले, तो वह केवल अस्तित्व की नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की भी विजय होती है।

आज वड्डा घल्लूघारा को याद करना केवल अतीत के घावों को कुरेदना नहीं है। यह उस इतिहास को समझने का प्रयास है, जिसने सिख समुदाय को वह बनाया, जो वह आज है। यह स्मरण हमें बताता है कि हिंसा और उत्पीड़न चाहे कितने ही भीषण क्यों न हों, वे किसी समुदाय की आत्मा को अनिवार्य रूप से नष्ट नहीं कर सकते।

वड्डा घल्लूघारा की स्मृति सिखों के लिए चेतावनी भी है और प्रेरणा भी। चेतावनी इस अर्थ में कि स्वतंत्रता और पहचान की रक्षा के लिए निरंतर सजग रहना आवश्यक है, और प्रेरणा इस अर्थ में कि सबसे गहरे अंधकार के बाद भी पुनर्जागरण संभव है। यह इतिहास का वह पाठ है, जो केवल सिखों तक सीमित नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए प्रासंगिक है।

इस प्रकार, वड्डा घल्लूघारा केवल एक तिथि या एक घटना नहीं है। यह पीड़ा, साहस, बलिदान और पुनर्निर्माण की सामूहिक कथा है।

यह उस सच्चाई का प्रमाण है कि जब किसी समुदाय की जड़ें विश्वास, एकता और आत्मसम्मान में गहरी हों, तो सबसे भीषण विनाश भी उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

गणेश कुमार शर्मा : जम्मू-कश्मीर की शिल्प विरासत, विश्व मंच पर भारतीय कला का गौरव

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर/जम्मूरू जम्मू के प्रसिद्ध मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा ने अपनी अद्भुत कला प्रतिभा और निरंतर साधना से न केवल जम्मू–कश्मीर बल्कि पूरे भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय कला जगत में रोशन किया है। उनकी मूर्तियाँ आज विश्व के कई देशों में निजी और सार्वजनिक संग्रहों की शोभा बढ़ा रही हैं।

गणेश कुमार शर्मा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, टेराकोटा और देवदार व शीशम जैसी लकड़ियों पर समान दक्षता के साथ काम करते हैं। उनकी रचनाएँ प्रकृति और मानव जीवन से प्रेरित होती हैं, जिनमें शक्ति, संवेदना और काव्यात्मक भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। चार दशक से अधिक के अपने लंबे कला–सफर में उन्होंने मूर्तिकला को एक नई पहचान दी है।

1991 में एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, शर्मा का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया और पूरी लगन के साथ अपने शिल्प को आगे बढ़ाया। आज वे कई उभरते कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

गणेश कुमार शर्मा को भारत और विदेशों से अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

उन्हें अमेरिका से दो बार गोल्ड मेडल, जम्मू–कश्मीर सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार (1998) सहित कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उन्हें अमेरिका, इराक, मिस्र, तुर्की, जर्मनी और इटली जैसे देशों की संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया है।

अपनी कला उपलब्धियों के साथ–साथ उनकी सादगी, विनम्रता और मानवीय गुण उन्हें एक महान कलाकार के साथ–साथ एक श्रेष्ठ इंसान भी बनाते हैं।

गणेश कुमार शर्मा आज सही मायनों में जम्मू–कश्मीर की धरोहर और विश्व की पहचान बन चुके हैं।

एआई फॉर ऑल : महिलाओं, युवाओं और कार्यबल के लिए एक समावेशी भविष्य का निर्माण

श्रीमती कविता भाटिया

जैसे–जैसे भारत वर्ष 2026 में होने वाले इंडियादृएआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की ओर बढ़ रहा है, सबसे प्रभावशाली कहानियाँ एल्गोरिद्म या स्वचालन (ऑटोमेशन) की नहीं, बल्कि समावेशन (इन्क्लूज़न) की हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कृत्रिम मेधा (एआइ) की वास्तविक शक्ति मानव क्षमता को बढ़ाने में निहित हैकृ विशेषकर महिलाओं, अनौपचारिक (इनफ़ॉर्मल) श्रमिकों और युवाओं के लिए, जो लंबे समय से औपचारिक अर्थव्यवस्था के हाशिये पर रहे हैं।

"मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया" के विज़न से प्रेरित होकर, मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियाएआई मिशन को स्वीकृति दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाइ) के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में, इंडियाएआई मिशन टीम ने रणनीतिक रूप से कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की और उनका क्रियान्वयन शुरू किया। इनमें इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी), इंडियाएआई डाटासेट्स प्लेटफ़ॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल, इंडियाएआई फ़्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फ़ाइनेंसिंग तथा सुरक्षित और विश्वसनीय एआई शामिल हैं।

मिशन का समावेशी विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ भारत की विविध सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और क्षेत्र–विशिष्ट आधारभूत मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जीपीयू ग्रिड के माध्यम से प्रशिक्षित ये मॉडल महिलाओं उद्यमियों, किसानों, गिग वर्कर्स और छोटे खुदरा व्यापारियों की सेवा के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में काम करने वाले एआई सहायक, सूक्ष्म–सलाह (माइक्रो–एडवाइज़री) टूल्स और क्षेत्र–विशेष ज्ञान इंजन विकसित हो रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर एआई को अक्सर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा प्रभाव काम, शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों तक लोकतांत्रिक पहुँच बनाने में हो सकता है। यही दृष्टि फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले इंडियादृएआई इम्पैक्ट समिट के केंद्र में होगी। नीति–निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक मंच पर लाकर, यह समिट "लोगों, प्रगति और पृथ्वी" के लिए एआई के उपयोग पर सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाएगा।

भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाएँ एक नए डिजिटल कार्यबल को आकार दे रही हैं, जिसे एआई सशक्त बना रहा है। एआई–आधारित बाज़ारों का उपयोग करने वाली महिला उद्यमी हों या एआई–संचालित सुरक्षा प्रणालियों के सहारे सुरक्षित रूप से काम करने वाली महिला ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनरकृतकनीक चुपचाप उनके लिए अवसर और स्वायत्तता (एजेंसी) बढ़ा रही है। उदाहरण के तौर पर, ब्यूटी और वेलनेस प्लेटफ़ॉर्म एआई–आधारित मिलान एल्गोरिद्म का उपयोग कर ग्राहकों को सेवा–प्रदाताओं से दूरी, कौशल और पूर्व प्रदर्शन के आधार पर जोड़ते हैं। इनमें अधिकांश सेवा–प्रदाता महिलाएँ हैं, जिन्हें अब लचीले कार्य घंटे, अनुमानित आय और एआई–सक्षम सत्यापन व ट्रैकिंग से बेहतर सुरक्षा मिल रही है। इसी तरह, राइड–हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म ने रियल–टाइम लोकेशन शेयरिंग और वॉइस–एक्टिवेटेड आपात सुविधाओं जैसी बुद्धिमान सुरक्षा प्रणालियाँ एकीकृत की हैं, जिससे महिला ड्राइवर अधिक आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ काम कर पा रही हैं। यद्यपि ये प्रणालियाँ पहले भी मौजूद थीं, लेकिन एआई ने उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता को कई गुना बढ़ा दिया है।

ग्रामीण और अर्ध–शहरी भारत में एआई–सक्षम वित्तीय उपकरण डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय भाषाओं में काम करने वाले एआई सहायक और वॉइस–आधारित डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ साक्षरता और भाषा की बाधाओं को कम कर रही हैं, जिससे महिलाएँ अपने वित्तीय निर्णय स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से ले पा रही हैं।

भारत के युवाओं के लिए एआई केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि नई अर्थव्यवस्था में प्रवेश का द्वार है। विभिन्न राज्यों में सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से एआई–कुशल प्रतिभाओं की एक सशक्त पाइपलाइन तैयार की जा रही हैकृजिसमें बुनियादी डिजिटल साक्षरता से लेकर उन्नत मशीन लर्निंग तक शामिल है। हाल ही में भारत सरकार ने इंडियाएआई मिशन के तहत युवा एआई फॉर ऑल राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस से जुड़ा यह अभियान एक संक्षिप्त, स्व–गति (सेल्फ–पेस्ड) "एआई 101" पाठ्यक्रम के माध्यम से लाखों छात्रों और युवा शिक्षार्थियों में एआई की आधारभूत समझ विकसित करने का लक्ष्य रखता है। स्कूलों, उच्च शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर, यह पहल एआई साक्षरता को एक विशिष्ट कौशल के बजाय जीवन–कौशल के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों के युवा एआई–आधारित अर्थव्यवस्था में सार्थक भागीदारी कर सकें।

एआई का समावेशी प्रभाव रोजगार से आगे बढ़कर सार्वजनिक कल्याण तक फैला है। मायगेट और सेफ़हाउस टेक जैसे स्टार्टअप एआई–आधारित विश्लेषण से आवासीय और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।

एआई–संचालित शिकायत निवारण प्रणालियाँ 112 इंडिया जैसी सरकारी हेल्पलाइनों में एकीकृत की जा रही हैं, जिससे आपात सेवाओं की प्रतिक्रिया समय में सुधार और डेटा–आधारित तैनाती संभव हो रही है।

कृषि क्षेत्र में किसान एआई जैसे टूल्स मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से कीट प्रकोप और मौसम–संबंधी जोखिमों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिससे महिला किसान अधिक सूचित और लचीले निर्णय ले पा रही हैं।

इसी प्रकार, इंडिफ़ी और किनारा कैपिटल जैसे फ़िनटेक नवप्रवर्तक एआई–आधारित क्रेडिट स्कोरिंग के ज़रिए महिला–नेतृत्व वाले उद्यमों को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, जिन्हें पहले औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक सीमित पहुँच मिलती थी।

यह दृष्टि नीति आयोग की रिपोर्ट "समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई" में भी परिलक्षित होती है, जो दर्शाती है कि एआई किस प्रकार भारत के लगभग 49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और वित्तीय समावेशन तक बेहतर पहुँच दिला सकता है।

जैसे–जैसे एआई आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में गहराई से एकीकृत हो रहा है, इसका नैतिक और समावेशी उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। "एआई फॉर ऑल" के सिद्धांत पर आधारित भारत का दृष्टिकोण निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित है, ताकि तकनीक असमानता बढ़ाने के बजाय अवसरों को बढ़ाए। भुगतान, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रोज़मर्रा के प्लेटफ़ॉर्म में एआई को समाहित कर भारत एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

भारत ने डिजिटल श्रमसेतु नामक एक राष्ट्रीय मिशन भी लागू किया है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों के एकीकरण पर केंद्रित है। इसका क्रियान्वयन चार स्तंभों पर आधारित हैकृक्षेत्र या पात्र–विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान, राज्यों को क्रियान्वयन के लिए सशक्त बनाना, सक्षम नियामक वातावरण तैयार करना और लागत कम करने व व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए साझेदारियाँ बनाना। यह पहल सरकार, व्यवसायों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एक कठोर प्रभाव–मापन प्रणाली के अंतर्गत एक साथ लाएगी।

सुलभता और समानता का यह मॉडल वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का एक प्रभावी खाका प्रस्तुत करता है।

यदि डिजिटल इंडिया और यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) द्वारा संचालित भारत की डिजिटल क्रांति की पहली लहर ने नागरिकों को जोड़ा, तो अगली लहर को एआई के माध्यम से उन्हें अवसरों से जोड़ना होगा। इसका अर्थ है ऐसे सिस्टम बनाना जो बहुभाषी, लैंगिक–संवेदनशील और सुलभ होंकृजहाँ ग्रामीण महिला उद्यमी, नागालैंड का डेटा लेबलर और भोपाल का युवा कोडर, सभी भारत के एआई भविष्य में समान हिस्सेदार हों।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

मुगलों की रसोई से क्या-क्या निकला जो दुनियाभर में फेमस हो गया?

मुगलों ने भारत में सिर्फ ऐतिहासिक निर्माण ही नहीं कराए, बल्कि कई जायकेदार व्यंजन भी दिए. शाही टुकड़े से लेकर नवरतन कोरमा तक और मुगलई पराठे से लेकर हलीम तक, ये मुगलों की शाही रसोई से निकले और वर्ल्ड फेमस हो गए. जानिए, मुगलों की रसोई से क्या-क्या निकला.

दिनेश पाठक

भारतीय खान–पान की दुनिया दीवानी है और बात जब मुगलों की हो तो शाही अंदाज और शाही खान–पान सहसा मन में कौंध जाता है. मुगल भारत आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति तो लाए ही, अपना खान–पान भी लेकर आए. चूंकि मुगलों का संबंध मध्य एशिया से लेकर फारस तक से था तो इनके मिश्रण से बने खान–पान को मुगलिया खान–पान का दर्जा मिला. आइए जान लेते हैं कि मुगलों की शाही रसोई से खाने–पीने की क्या–क्या चीजें मिलीं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं?

साल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी. मुगलों का शासन शुरू हुआ तो उनका खान–पान भी शाही रसोई में महकने लगा. इनमें जो सबसे चाव से खाया जाने वाला व्यंजन था, वह था बिरयानी.

जायकेदार बिरयानी

आज जो बिरयानी पूरी दुनिया में चाव से खाई जाती है, कम से कम भारत से उसका परिचय मुगलों ने ही करवाया था. बिरयानी चावल का मसालेदार पकवान होता है, जिसमें मांस, सीफूड और सब्जियां मिलाकर पकाया जाता है. बिरयानी में आमतौर पर बासमती चावल के अलावा मसालों में जावित्री, जायफल, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी–बड़ी इलायची, तेजपत्ता, धनिया, अदरक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है. इसे देशी घी में पकाने की परंपरा रही है. इसको दही, चटनी, रायता, कोरमा, करी, उबले अंडे और सलाद के साथ परोसा जाता है.

अब तो भारत के अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग जायकों वाली बिरयानी मिलती है. इन इलाकों में बिरयानी पकाने का तरीका भी अलग है. इसके कारण इनको इलाके के हिसाब से पहचाना जाता है. उदाहरण के लिए हैदराबादी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, सिंधी बिरयानी और मालाबार बिरयानी. बिरयानी के ही शाकाहारी रूप को तहरी कहा जाता है.

कबाब के क्या कहने

कबाब भी मुगल अपने साथ लेकर आए थे. इसके लिए मांस के छोटे–छोटे टुकड़े धागे में पिरो. कर ग्रिल पर पकाए जाते हैं. इससे कबाब बनाया जाता है. मुगल शासक अपने साथ कबाब की एक–दो नहीं, ढेरों रेसिपी लेकर आए. इनमें सींक कबाब, शिकमपुर कबाब और रेशमी कबाब काफी प्रसिद्ध हैं. इन्हें अलग–अलग तरह की सामग्री के साथ पकाया जाता है.

हलीम या खिचड़ा

मुगलों की ही देन है हलीम, जिसे भारत में खिचड़ा भी कहा जाता है. यह मूल रूप से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और उत्तरी इराक का प्रसिद्ध व्यंजन है. आज यह भारत के हैदराबाद, तेलंगाना, औरंगाबाद और महाराष्ट्र के कई शहरों में काफी लोकप्रिय है. इसे गेहूं, दाल, जौ, अलग–अलग मसालों और कीमा से तैयार किया जाता है. इसे पकाने में सात–आठ घंटे लगते हैं.

ऐसे ही मसालों के साथ पका कर तैयार की गई गाढ़ी तरी को करी कहा जाता है. यह भी मुगल अपने साथ लेकर आए थे. इसका इस्तेमाल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के व्यंजनों में किया जाता है. चिकन करी और अंडा करी तो काफी प्रसिद्ध है. करी की अलग–अलग कई तरह की रेसिपी मुगलों की देन है.

नवरत्न कोरमा और मुर्ग मुसल्लम

मुगलों की देन नवरतन कोरमा एक ऐसा व्यंजन है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरीके से बनाया जाता है. इसे नौ अलग–अलग सामग्री मिलाकर पकाया जाता है. वास्तव में यह एक बेहद स्वादिष्ट करी वाला व्यंजन है. इसमें ढेरों सूखे मेवे, सब्जियां, फल, क्रीम और सुगन्धित मसाले मिलाए जाते हैं. मुगलों का एक और पसंदीदा व्यंजन है मुर्ग मुसल्लम. इसमें पूरा मुर्गा अंडे, टमाटर, प्याज, अदरक, केसर, दालचीनी, खसखस, लौंग, मिर्च और इलायची जैसे मसालों को भरकर पकाया जाता है. मटन पसंद और रोगन जोश जैसे व्यंजन भी मुगलों की ही देन माने जाते हैं.

मुगलई पराठा.

रोटी और मुगलई पराठा

यह बात कौन मानेगा भला कि हर घर में बनने वाली रोटी अपने साथ मुगल लेकर आए थे. आमतौर पर गेहूं के आटे को गोल बेलकर तवे पर पकाई जाने वाली रोटी सब्जी के साथ परोसी जाती है.

इसी तरह से मुगलई पराठे की भी खूब चर्चा होती है. दरअसल, मुगलई पराठा स्वादिष्ट और नरम तला पराठा होता है. इसे गेहूं के आटे में कीमा, अंडा, प्याज, हरी मिर्च और काली मिर्च सहित कई अन्य सामग्री भरकर तैयार किया जाता है. बंगाल में तो आज सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड मुगलई पराठा है.

शर्बत और आइसक्रीम

गर्मियों में गला तर करने वाला शर्बत हो या फिर बच्चों की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम, दोनों ही मुगलों की देन हैं. शर्बत को फलों के रस, चीनी और पानी को मिलाकर बनाया जाता है. मुगल अपने साथ शरबत बनाने की कई विधियां लाए थे. शर्बत में गुलाब, केसर के साथ ही कई तरह के फ्लेवर का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से दूध और चीनी के साथ तरह–तरह के फ्लेवर और ड्राई फ्रूट आदि को मिलाकर तैयार की जाने वाली आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद है. सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय डेजर्ट में से एक आइसक्रीम के स्वाद से मुगलों ने ही हमें परिचित कराया.

मिठाइयां

मुगल अपने साथ कई तरह की मिठाइयां भी लेकर आए. इनमें से एक लोकप्रिय मिठाई है गुलाब जामुन. इसके लिए दूध से खोवा मावा तैयार किया जाता है. फिर देसी घी में तलकर चाशनी में डुबोया जाता है. इसके अलावा आज अलग–अलग ढंग से खाया जाने वाला पान भी मुगल मिठाई के रूप में भी इस्तेमाल करते थे. इसे खाने के बाद पाचक के रूप में खाया जाता था. शीर खुरमा और शाही टुकड़ा जैसी मिठाइयां भी मुगलों की ही देन हैं.

Helpline

पुलिस स्टेशन	
बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन	
बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रसोई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मदन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

नशा तस्करी के खिलाफ जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 मामले दर्ज, लाखों की संपत्ति और नकदी जब्त

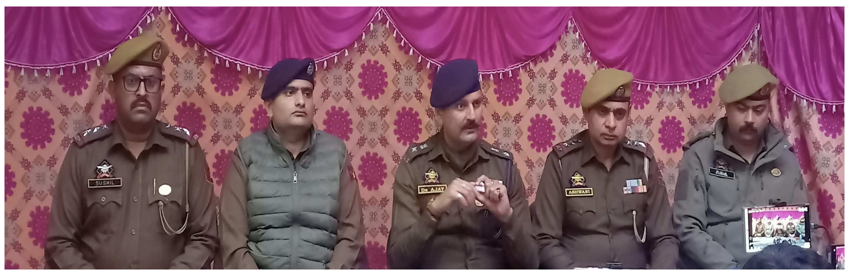

सबका जम्मू कश्मीर

सबका जम्मू कश्मीर (रोहित शर्मा)
जम्मू, 05 फरवरीरू जम्मू पुलिस साउथ जोन ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजीव नगर, बहू फोर्ट और बाग–ए–बहू क्षेत्र में सक्रिय ड्रग नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। बहू फोर्ट थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी साउथ जम्मू ने बताया कि पुलिस द्वारा पिछले एक वर्ष से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 से अब तक 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस दौरान 1 किलो 238 ग्राम हेरोइन और 18 किलो गांजा बरामद किया गया, जबकि 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नशा तस्करी में शामिल 11 लोगों के मकान सिविल प्रशासन द्वारा गिराए गए हैं। पुलिस ने 3 बैंक खाते फ्रीज किए, एक वाहन जब्त किया और करीब 25 लाख रुपये की अवैध कमाई भी जब्त की है।

हाल ही में बहू फोर्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पाल सिंह नामक आरा. ेपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की। जांच के दौरान सामने आया कि नशे के पैसे से संपत्ति का सौदा किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 21 लाख रुपये अपराध की कमाई के रूप में जब्त किए हैं।

वहीं, बाग–ए–बहू थाना पुलिस ने नाका चे. कंग के दौरान अरुण सिंह उर्फ काना को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हेरोइन और डिजिटल तराजू बरामद हुआ।

पूछताछ में कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने उनके बैंक खाता. े की जांच शुरू की। जांच में कुछ खातों में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के संदिग्ध लेन–देन पाए गए हैं। इनमें कुछ खाते हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संचालित होने की जानक. ारी मिली है।

एसपी साउथ ने कहा कि जम्मू पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें।

कठुआ की छात्रा चाहत ने 'परीक्षा पे चर्चा' में लिया हिस्सा, जिले का नाम किया रोशन

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, 06 फरवरीरू कठुआ की छात्रा मिस चाहत का चयन नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें देशभर के छात्र–छात्राओं को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में परीक्षा, शिक्षा और छात्रों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

मिस चाहत आर्मी पब्लिक स्कूल जंग्लोटे, कठुआ की छात्रा हैं। उनके साथ एस्कॉर्ट टीचर के रूप में सरकारी मिडिल स्कूल कठुआ की अध्यापिका सुश्री मोनिका खोसला भी मौजूद रहीं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका मार्गदर्शन किया।

राष्ट्रीय स्तर पर हुई चयन प्रक्रिया के बाद सीमित संख्या में छात्रों को चुना गया, जिसमें जम्मू–कश्मीर से चाहत एकमात्र छात्रा रहीं।

इस उपलब्धि से कठुआ जिले का नाम रोशन हुआ है। 'परीक्षा पे चर्चा' का उद्देश्य छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना और पढ़ाई के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ केवल कृष्ण ने छात्रा और उनके अभिभावकों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जेकेएससीईआरटी, निदेशालय स्कूल शिक्षा जम्मू और समग्र शिक्षा जम्मू–कश्मीर ने भी इस उपलब्धि की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में कांग्रेस का ज्ञापन, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ ने शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट कठुआ को एक ज्ञापन सौंपकर मनरेगा (डळछत्ल्ळ।) को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया और जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग उठाई।

ज्ञापन में कहा गया कि मनरेगा एक कानूनी अधिकार है और इसे किसी भी रूप में कमजोर करना या इसके मूल स्वरूप में बदलाव करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जिले की विभिन्न ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पास कर मनरेगा को उसके पुराने स्वरूप में लागू रखने की मांग की है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी से लोगों में नाराजगी है। लोगों का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और जनता का शासन पर विश्वास बढ़ेगा।

जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से मांग की कि ग्राम सभाओं के प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाए और इस ज्ञापन को बिना बदलाव के जम्मू–कश्मीर सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाया जाए।

कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा के कमजोर होने और राज्य का दर्जा न होने के कारण लोगों को रोजगार, आजीविका और अन्य सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बेरोजगारी और पलायन की समस्या बढ़ रही है।

20.37 लाख रूपए की संपत्ति जब्त, एनडीपीएस आरोपी पर राजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू/राजौरी, (अनिल भारद्वाज)जम्मू–कश्मीर के राजौरी जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस मामले में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्ति एक मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित कीमत 20,37,970 रूपये बताई गई है।

यह संपत्ति नाहिद चौधरी पुत्र मोहम्मद शफी, निवासी रामपुर तलवाल (पीर कंजू), तहसील व जिला राजौरी की है। राजौरी पुलिस थाना द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68–एफ के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई। उक्त आरोपी को थाना राजौरी में दर्ज एफआईआर संख्या 605/2025 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 8, 21, 22 व 29 में गिरफ्तार किया गया है।

राजौरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती भी शामिल है।

जूनियर क्रिकेट चौंपियनशिप : तीसरे दिन खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल, चढ़वाल और बिलावर फाइनल में पहुंचे

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला प्रशासन कठुआ द्वारा आबकारी विभाग के सहयोग से आयोजित जूनियर क्रिकेट चौंपियनशिप के तीसरे दिन कठुआ स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह लगातार बना हुआ है।

यह प्रतियोगिता युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल में मरहीन और चढ़वाल की टीम आमने–सामने रही। चढ़वाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। जवाब में मरहीन की टीम 143 रन ही बना सकी और मुक. ाबला एक रन से हार गई। मरहीन के सीरत ने 63 रन की शानदार पारी खेली।

दूसरे सेमीफाइनल में बिलावर और लखनपुर के बीच मुकाबला हुआ। बिलावर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। सुरजल ने 71 रन की बेहतरीन पारी खेली। लखनपुर की टीम जवाब में 115 रन ही बना सकी और बिलावर ने मैच जीत लिया।

अब चढ़वाल और बिलावर की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

डीएलटीसी कठुआ की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस मंजूर

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) कठुआ की बैठक अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) सुरिंदर मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2026द्27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित स्केल ऑफ फाइनेंस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें खेती की बढ़ती लागत और जिले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।

समिति ने चर्चा के बाद प्रस्तावित स्केल ऑफ फाइनेंस को व्यावहारिक और किसानों के हित में बताते हुए मंजूरी दे दी।

बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी, जेसीसी बैंक कठुआ के प्रतिनिधि, मुख्य बागवानी अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, जिला भेड़ पालन अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर अधिकारी, लीड जिला प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गुरू नाभादास जी के प्रकाश उत्सव की तैयारियों को लेकर 8 फरवरी को बैठक आयोजित

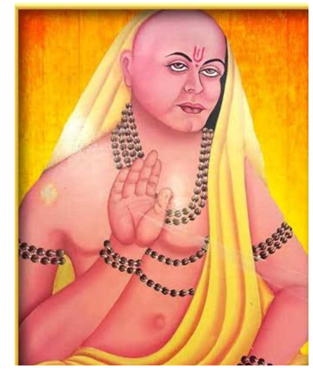

राम सिंह

गुरदासपुर : गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महासमिति पंजाब (रजि.) के आदेशानुसार 08 फरवरी 2026, रविवार को सुबह 11 बजे गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज जी के मंदिर, गांव हलला जिला गुरद. ासपुर में हंगामी बैठक आयोजित की जाएगी।

महासमिति के प्रधान श्री युद्धवीर सिंह ने बताया कि यह बैठक हर वर्ष की तरह इस साल 8 अप्रैल 2026 को मनाए जाने वाले गुरु नाभादास जी के प्रकाश उत्सव और शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर रखी गई है।

महासमिति की ओर से गुरु महाराज के सभी श्रद्धालुओं, समिति सदस्यों और भक्तों से बैठक में उपस्थित होकर कार्यक्रम की तैयारियों में सहयोग देने की अपील की गई है।

डीसी कठुआ ने शिक्षा क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की, समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता पर दिया जोर

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने शिक्षा क्षेत्र के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने गर्ल्स हाई स्कूल बिलावर, जीएचएसएस मन्हानपुर, जीएचएसएस मच्छेड़ी और जीएचएसएस कठेरा में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को काम में आ रही बाधाओं को दूर कर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में एचएसएस खरोते और मिडिल स्कूल चक शेखान के भवन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई और जल्द समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

वर्ष 2025द्26 के प्रस्तावित कार्यों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण, एचएसएस सनंगत्स और एचएसएस रौलका के भवन निर्माण तथा एचएसएस हीरानगर के रीमॉडलिंग कार्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने समग्र शिक्षा और यूटी कैपेक्स के तहत चल रहे सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के हित प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर, एसीडी अखिल सदोत्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी केवल कृष्ण, डीईपीओ अंजना मन्याल, सहायक निदेशक योजना दविंदर सिंह, एक्सईएन, जोनल शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

पीरपंजाल को लेकर मंत्री सुनील शर्मा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जम्मू-पुंछ सड़क जाम कर प्रदर्शन

सबका जम्मू कश्मीर

राजौरी, (अनिल भारद्वाज) एलओपी सुनील शर्मा द्वारा सदन में दिए भाषण में पीर पंजाल को लेकर दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजौरी में भारतीय जनता पार्टी व एलओपी सुनील शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआर अंबेडकर पार्क राजौरी से मुख्य सड़क मार्ग विरोध प्रदर्शन किया गया और एन एच 144बी को जाम कर प्रदर्शन कर सुनील शर्मा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस बल मौजूद था।

राजौरी में प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे

कांग्रेस जिला प्रधान अशोक शर्मा, एडवोकेट डालफी कुमार, युवा नेता अमित स्याल आदि ने कहा कि पीर पंजाल क्षेत्र ने बलिदान दिए हैं। उन्होंने कबीलेयिों और आतंकवादियों का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। विपक्ष के नेता ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर लोगों को बांटनेष और ष्नफरत के बीज बोनेष का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील शर्मा कुछ पता नहीं हैं। उनके अपशब्दों से खिता पीरपंजाल के लोगों को ठेंस पहुंची है। वहीं उधर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक राजौरी इफ्तिखार अहमद ने कहा कि एलओपी सुनील शर्मा राजौरी पुंछ के लोगों को अपमानित किया है। जिसे सहन नहीं किया जाएगा

पीर पंजाल के लोगों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और सुनील ने पीर पंजाल के ष्शहीदों का अपमानष किया है। और जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

बतादें कि ऐलओपी सुनील शर्मा ने राजौरी और पुंछ जिलों को पीर पंजाल क्षेत्र का हिस्सा बताए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा कि जम्मू-कश्मीर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसे उन्होंने एक अविभाजित इकाई बताया। जम्मू-कश्मीर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रीय पहचान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता को चुनौती देते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र को पहले "चंद्रभागा डिवीजन" कहा जाता था। उन्होंने कुछ तत्वों पर अलग-अलग क्षेत्रीय नामकरण को बढ़ावा देकर क्षेत्र की पहचान को "मिटाने या बदलने" का आरोप लगाया।

शर्मा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के प्रयासों से जम्मू-कश्मीर एक इकाई के रूप में गठित हुआ था और वर्तमान क्षेत्र को उनकी विरासत बताया। उन्होंने कहा था कि यदि कोई पुनर्गठन या आधिक. ारिक नामकरण अपनाया जाना है, तो इसे औपचारिक रूप से करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कठुआ क्रिकेट लीग : जूनियर क्रिकेट चौंपियनशिप में लखनपुर और बिलावर सेमीफाइनल में पहुंचे

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला प्रशासन कठुआ और आबकारी विभाग के सहयोग से आयोजित जूनियर क्रिकेट चौंपियनशिप का दूसरा दिन कठुआ स्टेडियम में उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता कठुआ क्रिकेट लीग के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश देना है।

दूसरे दिन दो मुकाबले खेले गए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय लोग स्टेडियम पहुंचे।

पहले मैच में लखनपुर और नगरी की टीम आमने-सामने हुई। लखनपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और नगरी को 47 रनों पर रोक दिया। इसके बाद लखनपुर ने लक्ष्य को तीन ओवर में हासिल कर आसान जीत दर्ज की।

दूसरे मैच में सलान और बिलावर के बीच मुकाबला हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिलावर ने 118 रन बनाए। जवाब में सलान की टीम 78 रनों पर ऑल आउट हो गई और बिलावर ने मैच जीत लिया।

इस जीत के साथ लखनपुर और बिलावर की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जो कल खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज, हीरानगर में हस्तशिल्प कौशल पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर/कठुआ। राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज, हीरानगर में संस्थान नवाचार परिषद एवं उन्नत भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में हस्तशिल्प कौशल को लेकर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान , कठुआ के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को हस्तशिल्प एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान एसबीआई रैम्ज कठुआ से आए संसाधन व्यक्ति श्री अविनाश एवं श्री अशोक ने विद्यार्थियों को विभिन्न हस्तशिल्प तकनीकों से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार पारंपरिक कला को अपनाकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। उन्होंने हस्तनिर्मित उत्पादों की बाजार में मांग और उनकी आर्थिक संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुश्री सोनिया एवं सुश्री बंधना ने अपने सफल अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को कौशल–आधारित प्रशिक्षण अपनाने और हस्तशिल्प को आय का साधन बनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्थानीय हस्तकलाओं, पारंपरिक कला संरक्षण और छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही कारीगरों के लिए उपलब्ध सरक. ारी योजनाओं और विपणन के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कौशल–आधारित शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी रचनात्मक क्षमताओं को रोजगार से जोड़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन प्रो. नीरू शर्मा ने किया, जबकि समापन अवसर पर डॉ. अनुपमा अरोड़ा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यशाला में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही, जिससे कार्यक्रम सफल एवं प्रेरणादायक बना।

जम्मू की स्तिथि के लिए हम जम्मू के लोग ही जिम्मेदार हैं

सबका जम्मू कश्मीर

2014 में पीडीपी के साथ जब बीज. `पी ने हाथ मिलाया था तो किसने किसके साथ गद्दारी की थी ? ये बात भी बतानी चाहिए जम्मू की जनता को...... मंत्री सतीश शर्मा जो जम्मू –कश्मीर के लिए पिछले 1.5 साल से तन–मन–धन और कड़ी मेहनत से अपने विभागों/मंत्रालयों का काम कर रहे हैं वो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है !

हम जम्मू वालों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने जम्मू के एक होनहार विधायक को मंत्री चुना और मंत्री सतीश शर्मा ने भी पिछले 1.5 सालों में अपने कामों से साबित भी किया है ! किसी ने ठीक ही कहा है हीरे की पहचान केवल जौहरी को ही होती है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वो राजनीति के जौहरी हैं अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की तरह जिन्होंने मुस्लिम कान्फ्रेंस को नैशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था कि जम्मूकश्मीर के दोनों संभागों को साथ लेकर ही शासन चलाया जा सकता है !

और हम लोग अपने ही बन्दे की टांग खिंचने में लगे हुए हैं इन्हीं वजहों के कारण पिछले 78 साला. ` में जम्मू संभाग, आतंकवाद से ग्रसित होते हुए भी कश्मीर संभाग की बराबरी नहीं कर पाया है और सोचो अगर कश्मीर में आतंकवाद ना होता तो कश्मीर संभाग भारत में नंबर एक पर होता !

जम्मू की ऐसी स्थिति के लिए हम जम्मू के लोग ही जिम्मेदार हैं कोई कश्मीरी या बाहरी नहीं !मेरी बातें कड़वी जरूर हैं पर सत्य पर आधारित हैं जिसे गहरायी से समझने की जरूरत है ! जय हिंद ! जय जम्मू–कश्मीर!

मेंढर में खेल स्टेडियम की मांग, युवाओं ने केंद्र सरकार से की अपील

राजेश कुमार

मेंढर – पुंछ : पुंछ जिले के मेंढर क्षेत्र में खेल सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों और युवाओं ने केंद्र सरकार से आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता जाहिर मन्हास और जाकिर मीर ने कहा कि मेंढर में बड़ी संख्या में युवा खेल गति. विधियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र के युवा फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों में सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक मेंढर में कोई मानक खेल मैदान या स्टेडियम नहीं है। खिलाड़ियों को खुले और असुरक्षित मैदानों में अभ्यास करना पड़ता है, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है।

जाहिर मन्हास और जाकिर मीर ने मांग की कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार मेंढर में एक बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम को मंजूरी दे। स्टेडियम में खेल मैदान के साथ–साथ बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग और खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार की खेल योजनाओं के तहत शुरू की जाए, ताकि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें और उनकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ने का मंच मिल सके।

एडीडीसी कठुआ ने एचएडीपी की प्रगति की समीक्षा की, सभी पात्र किसानों तक योजना पहुंचाने के निर्देश

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) कठुआ सुरिंदर मोहन शर्मा ने डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एचएडीपी) के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के विभिन्न घटकों और विभागों के कार्यों का जायजा लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि दक्ष किसान पहल के तहत कठुआ जिले ने केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसानों के पंजीकरण, प्रशिक्षण और कोर्स पूरा करने में जिले ने अच्छी प्रगति दर्ज की है।

बैठक में बीज उत्पादन, विशेष फसलों और सब्जियों को बढ़ावा, कृषि विपणन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मिलेट्स, कृषि मशीनीकरण और मशरूम उत्पादन सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूलों की खेती, तिलहन, एकीकृत कृषि प्रणाली और मृदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा हुई।

एडीडीसी सुरिंदर मोहन शर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने फील्ड स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यों की नियमित निगरानी पर जोर दिया, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।

बैठक में मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर सहित कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर
"पत्रकारों की आवश्यकता"
'सबका जम्मू कश्मीर' हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें
योग्यता:
- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- सोशल मीडिया घराने में काम करने का अनुभव
अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabkajammukashmir@gmail.com
संपर्क नंबर :
6005134383

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक संदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन
MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ कैंपस (जम्मू विश्वविद्यालय) में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जम्मू विश्वविद्यालय के कठुआ कैंपस में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए "बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की ओर यात्रा" विषय पर एक विशेषज्ञ सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और तनाव से निपटने के तरीके बताना था।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर एवं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ीं डॉ. संतोष कुमारी ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है और इसके लिए नियमित देखभाल और जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक सोच अपनाने के व्यावहारिक उपाय भी बताए।

आर्ट ऑफ लिविंग के राज्य समन्वयक श्री भगवती प्रसाद ने सुदर्शन क्रिया के लाभों के बारे में बताया और कहा कि यह तकनीक मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है।

कैंपस के रेक्टर प्रो. अरविंद जसरोटिया ने इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सभी की साझा जिम्मेदारी है। यूआईईटी के प्राचार्य डॉ. रॉकी गुप्ता ने छात्रों के लिए तनावमुक्त और सहयोगपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजन सचिव डॉ. सौरभ शास्त्री ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. विवुध गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. निशा चौधरी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कैंपस के विभिन्न विभागों के शिक्षक भी मौजूद रहे।

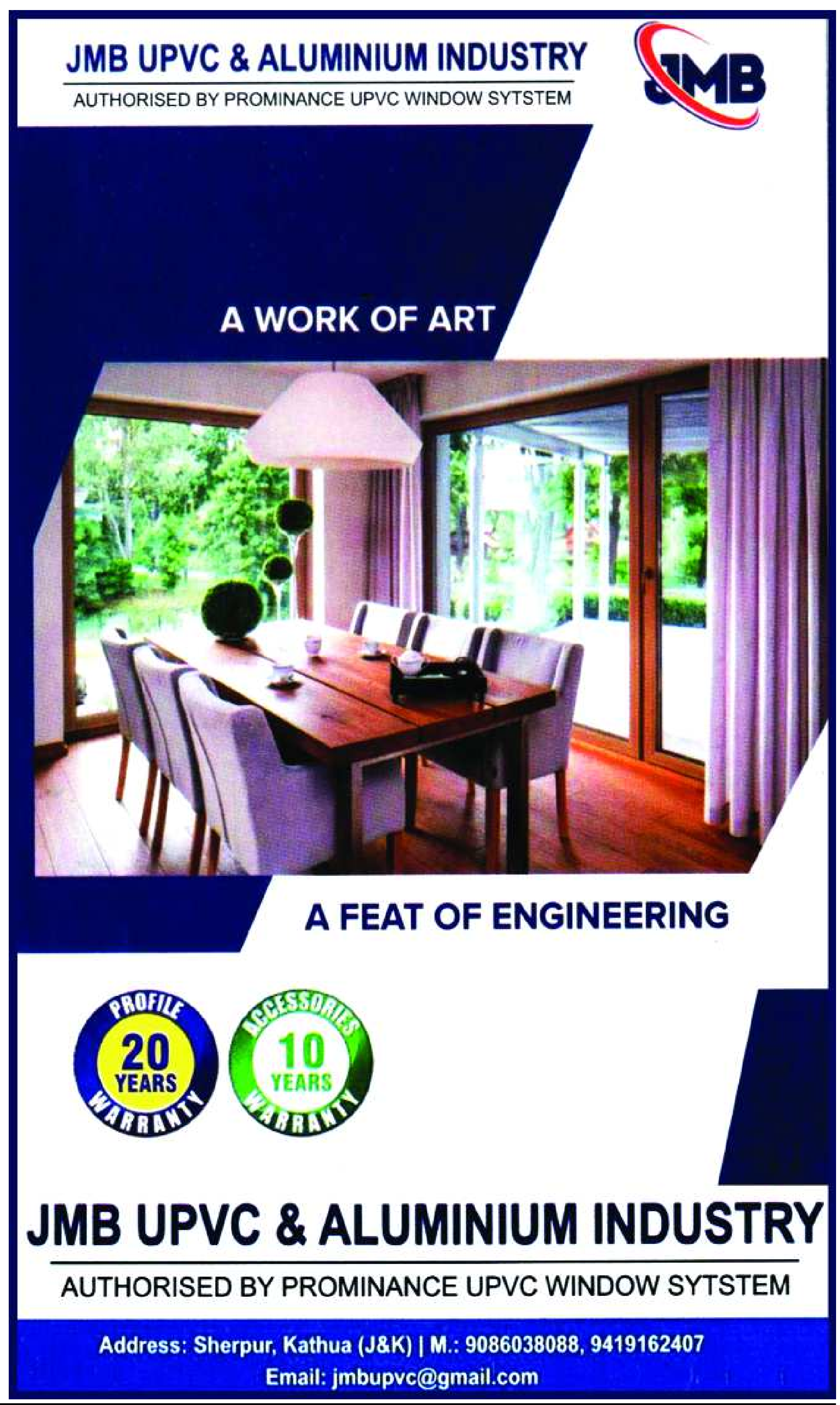

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नं: 184151 । संपादकः राज कुमार